

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

लं० 28] नई बिल्ली, जनिशार, जुलाई 11, 1970/आषाढ 20, 1892
 No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11, 1970/ ASADHA 20, 1892

इस पात्र में भिन्न पाठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अन्य संकरन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
 as a separate compilation

भाग II—ल०३ ३—उत्तरण (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(राजा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के नंदालयों और (संघ भेत्र प्रगति सर को छोड़कर)
 केन्द्रीय प्राविधिकरणों द्वारा जारी किये गये विविध ग्रांडेश और प्रधिकृत तंत्र।

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 17th June 1970

S.O. 2300.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagdish Singh, Village and P.O. Khadoor Sahib, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar, a contesting candidate for the mid-term general election held in February, 1969 to the Punjab Legislative Assembly from Khadoor Sahib Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagdish Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/16/69(21).]

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 1970

एस० ओ० 2300.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पंजाब विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में दुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए खद्दूर साहिब निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगदीश सिंह ग्राम एवं पो० खद्दूर साहिब, तहसील—तारन तारन, जिला—अमृतसर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा नवधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिकृत अपने निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दखिल करने में असफल रहे हैं।

ओर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तथा निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त जारण अथवा न्यायोचित नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एवं द्वारा उक्त श्री जगदीश सिंह को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस अधिकृत की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित घोषित करता है।

[स० पंजाब-वि० स०/16/69(21)]

S.O. 2301.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sant Singh, Village & P.O. Bharowal, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar, a contesting candidate for the mid-term general election held in February, 1969 to the Punjab Legislative Assembly from Khadoor Sahib Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sant Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/16/69(22).]

एस० ओ० 2301.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पंजाब विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में दुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए खद्दूर साहिब निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सन्त सिंह, ग्राम एवं पो० भारोवल, तहसील—तारन तारन, जिला—अमृतसर (पंजाब), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा नवधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिकृत अपने निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तथा निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायोचित नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एवं द्वारा उक्त श्री सन्त सिंह को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित घोषित करता है।

[स० पंजाब वि० म०/16/69(22)]

S.O. 2302.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tara Singh, Village & P.O. Khadoor Sahib, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar, a contesting candidate for the mid-term general election held in February, 1969 to the Punjab Legislative Assembly from Khadoor Sahib constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tara Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/16/69(23).]

एस० ओ० 2302.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पंजाब विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए खदूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तारा मिह, ग्राम एवं पा०—खदूर साहिब, तहसील—तरन सारान, जिला—श्रमूतसर (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार न, उसे सम्यक भूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के निए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री तारा मिह को नं सद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के मध्यम चुने जाने और हाने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[म० पंजाब-वि० स० / 16/69(23)]

S.O. 2303.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shyam Narain Sharma, S/o Shri Data Ram, R/o village Chandela, Post Office Bardaha, District Bijnor, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 151-Sheopur Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shyam Narain Sharma, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/151/69(51).]

एस० ओ० 2303.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 151-शिवपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्याम नरायण शर्मा सुपुत्र श्री दाता राम, निवासी गांव चन्देला, डा० बरदहा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचित आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचित आयोग एनदब्ल्यूआर उक्त श्री श्याम नरायण शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/151/69 (51)]

New Delhi, the 18th June 1970

S.O. 2304.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Habibur Rehman of village & P.O. Chatta, District 24-Parganas a contesting candidate for the mid-term election held in February, 1969, to the West Bengal Legislative Assembly from Basirhat Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Habibur Rehman to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/88/69(21).]

नई दिल्ली, 18 जून 1970

एस० ओ० 2304.—यतः, निर्वाचित आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचित के लिए बशीरहाट निर्वाचित-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हबीबुर रहमान, प्राप्ति० प०० छट्टा, जिला 24 परगना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचित व्यक्तों का नेतृत्व दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचित आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचित आयोग एनदब्ल्यूआर उक्त श्री हबीबुर रहमान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है।

[सं० प्र० वि० स०/88/69(21)]

S.O. 2305.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Satish Chandra Samanta, Village & P.O. Pancharul, Howrah (West Bengal), a contesting candidate for the mid-term election held in February, 1969, to the West Bengal Legislative Assembly from 166-Udaynarayanpur Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Satish Chandra Samanta to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/166/69(20).]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० ओ० 2305.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 166 उदयनारायणपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सतीश चन्द्र सामन्ता, ग्राम एवं पो० आ० पंचास्त, हावड़ा, (पश्चिमी बंगाल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्रूपीत बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

ओर, यतः, उक्त उम्मीदवार उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

यतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एन्डव्हारा उक्त श्री सतीश चन्द्र सामन्ता को मंसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है ।

[सं० प० ब०-वि० स०/166/69(20)]

आदेश से,

बी० नागसुभमण्णन, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th June 1970

S.O. 2306.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Third Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, for clause 3(ii), the following shall be substituted, namely:—

“(3)(ii) in the Navy, Director of Personnel, Director of Personal Services, Deputy Director of Personnel or Deputy Director of Personal Services, and”.

[No. 1/4/70-Pub.L.]

(गृह मंत्रालय)

नई दिल्ली, 30 जून, 1970

एम. ओ. 2306—संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त गवितयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 में और आगे संशोधन करते के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) ये नियम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) तृतीय संशोधन नियम 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख के प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम 1958 के नियम 2 में खण्ड 3(ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(3) (ii) नीसेना में कार्मिक-निदेशक, वयक्तिक सेवाओं का निदेशक, उप कार्मिक-निदेशक या वैयक्तिक सेवाओं का उप निदेशक और”

[सं. 3/4/70-पब्लिक-1]

New Delhi, the 4th July 1970

S.O. 2307.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Fourth Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, for clause (39) the following clause shall be substituted, namely :—

(39) in the case of orders and other instruments relating to the Union Public Service Commission, by the Secretary, Deputy Secretary or Under Secretary in charge of Administration, the Office of that Commission; or

[No. 3/3/70-Public.I.]
ASOKA SEN, Jt. Secy.

नई दिल्ली 4 जुलाई, 1970

का. ओ. 2307.—संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त गवितयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1959 में और आगे संशोधन करते के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) चतुर्थ संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1959 के नियम 2 में, खण्ड (39) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(39) संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आदेशों और अन्य लिखितों की दण में, उस आयोग के कार्यालय में सचिव, उपसचिव, या प्रशासन के भारसाधक ग्रंथालय सचिव द्वारा ; या

[सं. 3/3/70-पब्लिक-1]
अशोक सेन, संयुक्त सचिव :

New Delhi, the 1st July 1970

S.O. 2308.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 492 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), the Central Government hereby appoints Shri S. Govindaswaminathan, Advocate-General, Tamil Nadu, Madras as a Public Prosecutor for conducting the prosecution of the accused, in cases RC. 1/66/EOW/Madras and RCs 18 to 28/EOW/68-Madras in the original, appellate and revisional courts.

[No. 225/50/69-AVD(II).]

B. C. VANJANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जून 1970

ध्र० ध्र० 2308—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 492 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार तमिल नाडू, मद्रास के श्री एस० गोविन्दास्वामिनाथन्, महाधिकर्ता को मुकदमा मंरुया आर० सी० 1/66/ई०/ओ० डब्ल्य०/मद्रास तथा आर० साज० 18 से 28/ई०/ओ० डब्ल्य०/68 मद्रास में अभियुक्तों पर मुकदमे का संचालन करने के लिए मूल, अपीलीय और पुनरीक्षण व्यायालयों में लोक अभियोत्रक के रूप में एन्ड्रेश्वारा नियुक्त करती है।

[संख्या 225/50/69-प्र० स० प्र०-2]

बी० सी० वंजानी, अवर सचिव।

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

New Delhi, the 27th June 1970

S.O. 2309.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Legislative Department) No. 11/1/70-Waqf, dated the 3rd April, 1970, the Central Government, in consultation with the Durgah Committee, Ajmer, hereby appoints Mir Mustafa Ali Khan Saheb, as Nazim, Durgah Khawaja Saheb, Ajmer, for a further period of one year upto and inclusive of the 28th June, 1971.

[No. 11/1/70-WAQF.]

E. VENKATESWARAN, Dy. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 1970

एस० ध्र० 2309.—दरगाह खावाजा साहब अधिनियम 1955 (1955 का 36) की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार विधि मंत्रालय, विधायी विभाग का अधिसूचना सं० 11/1/70-वक्फ दिनांक 3 अप्रैल, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार दरगाह कमेटी, अजमेर से परभमण करके, एतद्वारा मीर मुस्नाफा श्री खां साहब को 28 जून, 1971 तक और सहित एक वर्ष की शारीर की कालावधि के लिए दरगाह खावाजा साहब, अजमेर के नजीम के रूप में, नियुक्त करती है।

[सं० 11/1/70-वक्फ]

ई० वेंकटश्वरत, उप सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 1st June 1970

S.O. 2310.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 35 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank, hereby exempts the State Bank of India for the period from the 14th January, 1970 to the 13th January, 1971 both days inclusive, from the provisions of clauses (a) and (c) of sub-section (1) of Section 34 of the said Act in so far as they preclude the State Bank of India from—

- (i) continuing or realising the advances against the security of immovable property made by the Kamala Bank Ltd., the Bengal Duars Bank Ltd., and the Raikut Industrial Bank Ltd. and taken over by the State Bank of India under the terms and conditions of acquisition by the State Bank of India of the business of the Kamala Bank Ltd., the Bengal Duars Bank Ltd., and the Raikut Industrial Bank Ltd., sanctioned under sub-section (2) of the said Section 35 by the Central Government by an order in writing dated the 15th October, 1966; and
- (ii) making against the security of immovable property against which the advances referred to above have been made such further advances as the State Bank of India may consider necessary or expedient for ensuring or facilitating the recovery of the advances made by the Kamala Bank Ltd., the Bengal Duars Bank Ltd., and the Raikut Industrial Bank Ltd., and realising such further advances.

[No. F. 4/5/70-SB.]

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून 1970

एस.ओ. 2310.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23 वां) की धारा 35 की उपधारा (7) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करके, एतद्वारा 14 जनवरी, 1970 से 13 जनवरी 1971 तक की अवधि के लिए, जिसमें ये दोनों दिन भी शामिल हैं, उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के द्वारा अमर (ग) उपबन्धों से, जहां तक कि वे भारतीय स्टेट बैंक को निम्नलिखित कार्य करने से रोकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक को छूट देती है:—

- (1) उन अग्रिमों को जारी रखना या बसूल करना जो कमला बैंक लिमिटेड, बंगाल दुआर्स बैंक लिमिटेड तथा रायकूट इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड द्वारा अचल सम्पत्ति की जमानत पर दिये गये थे और जिन्हें उक्त धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 1966 के लिखित प्रादेश के अनुभार स्वीकृत की गयी, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कमला बैंक लिमिटेड, बंगाल दुआर्स बैंक लिमिटेड तथा रायकूट इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड के व्यवसाय के अधिग्रहण किये जाने की शर्तों के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक के अपने हाथ में से लिया है; और
- (2) जिस अवल सम्पत्ति की जमानत पर उपर्युक्त अग्रिम दिये गये हैं उसकी जमानत पर, ऐसे और अग्रिम देना और बसूल करना जिन्हें कमला बैंक लिमिटेड, बंगाल दुआर्स बैंक लिमिटेड और रायकूट इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड के द्वारा दिये गये अग्रिमों की बसूली को सुनिश्चित और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक आवश्यक तथा उचित समझें।

[संख्या एफ. 4/5/70-एस बी.]

New Delhi, the 19th June 1970

S.O. 2311.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Kamrup District Central Co-operative Bank Ltd., Gauhati for a period of one year with effect from 1st March, 1970.

[No. F. 18/7/70-SB.]

नयी दिल्ली, 19 जून, 1970

एस० ओ० 2311.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का दसवां) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबन्ध कामरूप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि० गौहाटी पर, 1 मार्च, 1970 से एक वर्ष की प्रवधि तक लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 18/7/70-एस० बी०]

New Delhi, the 25th June 1970

S.O. 2312.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 19th June, 1970

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	22,49,46,000
		Rupee Coin	2,76,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	5,20,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	155,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
		(a) Internal	..
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	15,28,57,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	35,00,00,000	Balances Held Abroad*	101,44,55,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	75,00,00,000	Investments**	119,82,79,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government :—		(i) Central Government	..
(i) Central Government	193,14,21,000	(ii) State Governments @	190,55,96,000
		(iii) Scheduled Commercial Banks†	306,78,35,000
		(iv) State Co-operative Banks††	218,02,31,000
		(v) Others	5,30,05,000

		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund :—
(ii) State Governments	3,91,80,000	(a) Loans and Advances to :—
		(i) State Governments 38,77,80,000
		(ii) State Co-operative Banks 15,03,39,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures 9,65,70,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund :—
(i) Scheduled Commercial Banks	186,62,73,000	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	9,58,59,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks 4,57,87,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	71,18,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial
(iv) Other Banks	30,60,000	Credit (Long Term Operations) Fund :—
		(a) Loans and Advances to the Development Bank 11,26,71,000
(c) Others	97,89,03,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank
Bills Payable	37,68,55,000	Other Assets 53,92,83,000
Other Liabilities	158,17,61,000	
	Rupees 1108,04,30,000	Rupees 1108,04,30,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 137,14,35,000 advanced to Scheduled commercial banks against usance bills under section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 24th day of June, 1970.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 19th day of June, 1970.
 ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Notes held in the Banking Department	22,49,46,000	Gold Coin and Bullion :—	
Notes in Circulation	4081,14,13,000	(a) Held in India	182,53,11,000
Total Notes issued	4103,63,59,000	(b) Held outside India	..
TOTAL LIABILITIES	4103,63,59,000	Foreign Securities	401,42,00,000
		TOTAL	583,95,11,000
		Rupee Coin	52,15,01,000
		Government of India Rupee Securities	3467,53,47,000
		Internal Bills of Exchange and other commercial paper	..
		TOTAL ASSETS	4103,63,59,000

Dated the 24th day of June, 1970.

S. JAGANNATHAN,
 Governor.

[No. F 3(3)-BC/7.]

नई दिल्ली, 25 जून, 1970

एस. नं. 2312.—29 जून 1970 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुक्ता पूँजी	5,00,00,000	नोट	22,49,46,000
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,76,000
		छोटा सिक्का	5,20,000
		खरीदे और भुनाये गये बिल:—	
राष्ट्रीय कृषि क्षण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	155,00,00,000	(क) देशी	..
राष्ट्रीय कृषि क्षण (स्थिरीकरण) निधि	35,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय श्रीदोगिक क्षण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	75,00,00,000	(ग) सरक. री खजाना बिल विवेषों में रखा हुआ बकाया*	15,28,57,000
जमा रक्षियां:—		विवेष**	101,44,55,000
(क) सरकारी		क्षण और अग्रिम:—	119,82,79,000
(i) केन्द्रीय सरकार	193,14,21,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	3,91,80,000	(ii) राज्य सरकारों को@	190,55,96,000
(ख) बैंक		क्षण और अग्रिम:—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	186,62,73,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तो†	306,78,35,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	9,58,59,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡†	218,02,31,000
		(iii) दूसरों को	5,30,05,000

देयताएँ	रुपये	आस्तियां	रुपये
		राष्ट्रीय कृषि क्रण (दोर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से क्रण, अप्रिम और निवेश :—	
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	71,18,000	(क) क्रण और अप्रिम :— (i) राज्य सरकारों को	33,77,80,000
(iv) अन्य बैंक	30,60,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	15,03,39,000
(g) अन्य	97,89,03,000	(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को
देय विल	37,68,55,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिवेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि क्रण (स्थिरीकरण) निधि से क्रण और अप्रिम	9,65,70,000
अन्य देयताएँ	158,17,61,000	राज्य सहकारी बैंकों को क्रण और अप्रिम राष्ट्रीय औद्योगिक क्रण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से क्रण, अप्रिम और निवेश :—	4,57,87,000
		(क) विकास बैंक को क्रण और अप्रिम	11,26,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिवेंचरों में निवेश
		अन्य आस्तियां	53,92,83,000
रुपये	1108,04,30,000	रुपये	1108,04,30,000

*नकदी, आवधिक जमा और अन्यकालीन प्रतिमूलियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि क्रण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक क्रण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि क्रण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से प्रदत्त क्रण और अप्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 17(4) (g) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी विलों पर अप्रिम दिये गये 137,14,35,000 रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि क्रण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय कृषि क्रण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त क्रण और अप्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 24 जून, 1970।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जून, 1970 की 19 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा
इशु विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	22,49,46,000		सोन का सिक्का और बुलियन:—		
संचालन में नोट	403,114,13,000		(a) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
			(b) भारत के बाहर रखा हुआ		
जारी किए गए कुल नोट	4103,63,59,000		देशी प्रतिभूतियां	401,42,00,000	
			जोड़ . .		583,95,11,000
			रुपये का सिक्का		52,15,01,000
			भारत सरकार की रुपया		
			प्रतिभूतियां		3467,53,47,000
			देशी विनियम बिल और		
			दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयताएं . .	4103,63,59,000		कुल आस्तियां .		4103,63,59,000

तारीख: 24 जून, 1970।

एस० जगन्नाथन,
गवर्नर।

[स० एफ० 3 (3)–बी० सी०/70]

New Delhi, the 1st July 1970

S.O. 2313.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds the name of the National Institute of Bank Management, Bombay, to the Schedule to the said Act.

[No. F.7(10)-BC/70.]

नयी दिल्ली, 1 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2313.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 के 19वें) की धारा 8 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवंद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में बम्बई-स्थित राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान का नाम शामिल करती है।

[सं० एफ० 7(10)-बी० सी०/70]

S.O. 2314.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the National Institute of Bank Management, Bombay.

[No. F.7(10)-BC/70(1).]

एस० ओ० 2314.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 के 19वें) की धारा 8 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवंद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध बम्बई-स्थित राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान (नेशनल इन्स्ट-ट्रियूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट) के कर्मचारियों के लाभ के लिये स्थापित की गयी भविष्य निधि पर लागू होगे।

[सं० एफ० 7(10)-बी० सी०/70]

New Delhi, the 2nd July 1970

S.O. 2315.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply, from the 19th June, 1970 till the 1st February, 1971, to the under-mentioned bank in so far as the said provisions prohibit that bank's Custodian and/or Chief Executive Officer, by whatever name called, from being the director of the Agricultural Finance Corporation Ltd., which is a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Name of Bank.	Name and designation of Custodian/Chief Executive Officer.
1	2
1. Indian Overseas Bank, Madras	Shri R. N. Chettur, Custodian.

[No. F. 15(11)-BC/69.]

नयी दिल्ली, 2 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2315.—बैंकिंग विनियमन, 1949 (1949 का दसवां) की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एवंद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) और (ii) के उपबन्ध, निम्नलिखित बैंक पर, जहां तक वे उस बैंक के अधिरक्षक और या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, कृषि वित्त निगम लिमिटेड, जो

समवाय अधिनियम, 1956 (1956 का पहला) के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी है, के निदेशक बनते से रोकते हैं, उन्नीस जून 1970 से लेकर पहली फरवरी, 1971 तक लागू नहीं होंगे।

बैंक का नाम	अभिरक्षक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम तथा पद
1	2
इंडियन ओवरसीज बैंक, मद्रास	श्री आर० एन० चेत्तुर, अभिरक्षक

【सख्ता एफ० 15 (11)-वी० सी०/69】

New Delhi, the 3rd July, 1970

S. O. 2316.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 26th June, 1970.

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	45,75,41,000
		Rupee Coin	2,75,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	4,74,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	155,00,00,000	(a) Internal	..
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	10,23,38,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	35,00,00,000	Balances held Abroad*	105,27,95,000
		Investments**	112,34,01,000
National Industrial Credit (Long Term Operations Fund)	75,00,00,000	Loans and Advances to :—	
		(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	120,70,30,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks†	291,53,85,000
(i) Central Government	108,66,55,000	(ii) State Co-operative Banks††	215,57,85,000

(5) State Governments	6,72,91,000	(6) Others	2,69,30,000
Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund—			
(b) Banks		(a) Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	183,09,64,000	(i) State Governments	34,15,12,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	10,75,49,000	(ii) State Co-operative Banks	18,72,37,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	71,48,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv) Other Banks	25,76,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	9,65,70,000
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	4,48,93,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund:—	
(c) Others	94,69,96,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	11,26,71,000
Bills Payable	38,24,44,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
Other Liabilities	175,96,12,000	Other Assets	56,64,16,000
	Rupees. 1039,12,35,000		Rupees. 1039,12,35,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

(a) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 139,16,60,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

†† Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 1st day of July, 1970.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 26th day of June, 1970.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	45,75,41,000		Cold Coin and Bullion :-		
Notes in circulation	4020,18,33,000		(a) Held in India	182,53,11,000	
			(b) Held outside India	..	
Total Notes issued		4065,93,74,000	Foreign Securities	401,42,00,000	
			TOTAL	..	583,95,11,000
			Rupee Coin	..	54,44,58,000
			Government of India Rupee Securities	3427,54,05,000	
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper	..	
TOTAL LIABILITIES		4065,93,74,000	TOTAL ASSETS	..	4065,93,74,000

Dated the 1st day of July, 1970.

S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F. 3 (3)-BC/70.]

L. S. P. SARATHY, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई 1970

एस. नं. 2316.—26 जून 1970 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण।

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुक्ता पूँजी	5,00,00,000	नोट	45,75,41,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,57,000
		छोटा सिक्का	4,74,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	155,00,00,000	खरीद और भुताये यथे बिल :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्वीकरण) निधि	35,00,00,000	(क) देशी	
		(ख) विदेशी	
		(ग) सरकारी खजाना बिल	10,23,38,000
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	75,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	105,27,95,000
		निवेश**	112,34,01,000
जमा राशियां :—			
(क) सरकारी		ऋण और अप्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	108,66,55,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	
(ii) राज्य सरकारें	6,72,91,000	(ii) राज्य सरकारों को @	120,70,30,000
(ख) बैंक		ऋण और अप्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	183,09,64,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	291,53,85,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10,75,49,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	215,57,85,000
		(iii) दूसरों को	2,69,30,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से	
		ऋण, अप्रिम और निवेश :—	

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	71,48,000	(क) ऋण और अग्रिमः— (i) राज्य सरकारों को	34,15,12,000
(iv) अन्य बैंक	25,76,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	18,72,37,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिक्षक बैंकों को	..
(ग) अन्य	94,69,96,000	(ख) केन्द्रीय भूमिक्षक बैंकों के डिवैन्चरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	9,65,70,000
इय बिल	38,24,44,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय भौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	4,48,93,000
न्य देयताएं	175,96,12,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिवैन्चरों में निवेश अन्य आस्तियां	11,26,71,000 .. 56,64,16,000
	1039,12,35,000		1039,12,35,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय भौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

⑥राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

+रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 139,16,60,000
रुपये शामिल हैं।

†+राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

ग्राहीक : १ जुलाई, 1970।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जून 1970 की 26 तारीख को समाप्त हुए सम्पाद्य के लिये लेखा

इन्द्र विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	मास्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए			सोने का सिक्का और बुलियन		
नोट	45,75,41,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचलन में नोट	4020,18,33,000		(ख) भारत के बाहर रखा		
			हुआ		
			विदेशी प्रतिभूतियां	401,42,00,000	
प्रारंभिक रूपये का सिक्का			बोड़		583,95,11,000
प्रारंभिक रूपये का सिक्का			भारत सरकार की रुपया		54,44,58,000
प्रारंभिक रूपये का सिक्का			प्रतिभूतियां		3427,54,05,000
देशी विनियम विल और			दूसरे वाणिज्य पद्धति		
कुल देयताएं	4065,93,74,000	कुल मास्तियां		4065,93,74,000	

तारीख: 1 जूलाई, 1970।

एस० जगन्नाथन,
यवर्नर।

[स०. क० 3(3)-वी० सी०/70]
एल० एस० पी० सारथी, अनु-सचिव।

(Department of Banking)

New Delhi, the 29th June 1970

S.O. 2317.—In pursuance of the proviso to sub-section 5 of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the Central Government hereby appoints Shri N. Ramanand Rao as Custodian, Central Bank of India, with effect from the date he assumes charge, vice Shri V. C. Patel retired.

[No. F.4(40)-BC/70.]

S. S. SHIRALKAR, Addl. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नयी दिल्ली, 29 जून, 1970

एस० ओ० 2317 बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उप-धारा 5 के परन्तुक के अनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सेवानिवृत्त श्री वी० सी० पटेल के स्थान पर श्री एन० रामानन्द राव को, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, सेप्टेम्बर बैंक आफ इण्डिया का अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 4(40)-बी० सी०/70]

एस० एस० शिरालकर, अतिरिक्त सचिव

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 2nd June 1970

S.O. 2318.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri K. K. Veer who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This notification shall come into force on 8th June, 1970.

[No. 88(F. No. 404/110/70-ITCC).]

(राजस्व और बीमा विभाग)

(आयकर)

नई दिल्ली, 2 जून, 1970

एस० ओ० 2318 :—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, श्री के० के० वीर को, जो केन्द्रीय सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर-वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना 8 जून, 1970 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 88 (एफ० सं० 404/110/70-आई टी सी सी.)]

New Delhi, the 11th June 1970

S.O. 2319.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorise Shri J. S. Agarwal who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from 15th June, 1970.

[No. 97(F. No. 404/111/70-ITCC).]

E. K. LYALL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 जून, 1970

एस० ओ० 2319:—ग्रायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार श्री जे० एस० अप्रवाल को, जो केन्द्रीय सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर यस्ती अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्वारा प्राप्तिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना 15-6-70 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 97 (एफ० सं० 404/111/70-ग्राइंटी०सी०सी०)]

ई० के० लायल, उप सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 5th June 1970

S.O. 2320.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Sri Arunachaleswarar Devasthanam, Tiruvannamalai to be of archaeological and artistic importance for the purposes of the said section.

[No. 92 (F. No. 176/27/70-IT(AI).]

(राजस्व और बीमा विभाग)

(ग्रायकर)

नई दिल्ली, 5 जून, 1970

एस० ओ० 2320—ग्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 89-छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, श्री अरुणा चलेश्वर देवस्थानम, तिरुवन्नामलाई, को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा पुरातात्त्विक और कलात्मक महत्व का घोषित करती है।

[सं० 92 (एफ० सं० 176/27/70-ग्राइंटी (ए 1)]

S.O. 2321.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Shri Devanathaswamy Temple Cuddalore to be of archaeological and artistic importance for the purposes of the said section.

[No. 92 (F. No. 176/26/70-IT(AI).]

L. N. GUPTA, Under Secy.

एस० ओ० 2321:—ग्रायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, श्री देवनाथ स्वामी मंदिर, कुड्डालोर, को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा पुरातात्त्विक और कलात्मक महत्व का घोषित करती है।

[सं० 93 (एफ० सं० 176/26/70-ग्राइंटी (ए 1)]

एल० एन० गुप्ता, अश्रु सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 11th July 1970

S.O. 2322.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Shri M. Ramachandran as the Collector of Customs, Bombay.

2. The appointment of Shri M. Ramachandran made under paragraph 1 shall be without prejudice to the appointment of Shri G. S. Sawhney as the Collector of Customs, Bombay.

[No. 67/F. No. 22/5/70-Cus.IV.]

J. DATTA, Dy. Secy.

(राजस्व और सीमा विभाग)

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2322:—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० रामचन्द्रन को सीमा-शुल्क कलक्टर, मुम्बई के रूप में नियुक्त करती है।

2 श्री एम० रामचन्द्रन की पैरा 1 के अधीन की गई नियुक्ति का श्री जी० एस० सहनी को सीमाशुल्क कलक्टर, मुम्बई के रूप में नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[स० 67/फा० सं० 22/5/70/सीमा-शुल्क-4.]

ज्योतिर्मय दस, उप सचिव।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

INCOME-TAX

New Delhi, the 13th January 1970

S.O. 2323.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its Notification No. 38-Income-tax, dated the 27th May, 1969 namely:—

In the said schedule against 'A' and 'E' Range, Madras under Column 2, the following shall be substituted, namely:—

A-Range, Madras.

1. Company Circle II(all Sections), Madras.
2. City Circle I, Madras.
3. City Circle III, Madras.
4. City Circle V, Madras.
5. Foreign Section, Madras.
6. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Madras.
7. Tax Recovery Circle, Madras.

E-Range, Madras.

1. City Circle IV, Madras
2. City Circle VI, Madras.
3. City Circle VII (all Sections), Madras.
4. Vellore Circle.

This notification shall come into force on the 15th January, 1970.

Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of creation of 'Y'-Range, Calcutta, and consequent re-allocation of the AAC's jurisdiction in West Bengal Charge.

(This note does not form a part of Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 8(F. No. 261/2/70-ITJ).]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1970

एस० आ० 2323 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस तिमिस अपने को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा अपनी अधिसूचना सं० 58-आयकर^० तारीख 27 मई, 1969 से उपावद अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में 'क' और 'ड' रेंज मद्रास के सामने स्तम्भ 2 के नीचे निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

क—रेंज, मद्रास

1. कम्पनी संकिल ii समस्त अनुभाग, मद्रास ।
2. सिटी संकिल i, मद्रास ।
3. सिटी संकिल iii, मद्रास ।
4. सिटी संकिल iv, मद्रास ।
5. विदेश अनुभाग, मद्रास ।
6. संपदा शुल्क एवं आयकर संकिल, मद्रास ।
7. कर वस्त्री संकिल, मद्रास ।

ड—रेंज, मद्रास

1. सिटी संकिल iv, मद्रास ।
2. सिटी संकिल vi, मद्रास ।
3. सिटी संकिल vii (सब अनुभाग, मद्रास) ।
4. बैलोर संकिल ।

यह अधिसूचना 15 जनवरी, 1970 को प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण :—

यह संशोधन अपीली सहायक आयुक्तों के बीच कार्यों के पुनर्विंटन के कारण आवश्यक हो गया है ।

(उपरोक्त टिप्पण अधिसूचना का अंग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है) ।

[सं० 8 (फा० सं० 261/2/70-आईटीजे)]

New Delhi, the 20th January 1970

S.O. 2324.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes makes the following amendments in the schedule appended to its Notification No. 143(F. No. 50/42/69-ITJ), dated 24th October, 1969 viz:

In the said schedule (i) against B-Range, Jaipur under Column 2 after Addl. M-Ward, and before Jaipur the following shall be added namely—"Addl. H-Ward".

(ii) Against Kota Range, Kota in Column 2 in item 2 add after 'Bharatpur Circle' the following namely—

"A and B Wards, Bharatpur".

This Notification shall take effect from the 21st January, 1970.
Explanatory Note

The amendment has become necessary for assigning appellate jurisdiction over Addl. H-Ward, Jaipur and B-Ward, Bharatpur newly created Ward, with effect from 15th December, 1969 and 5th January, 1970 respectively and redesignation of the Income-tax Officer, Bharatpur as Income-tax Office, A-Ward, Bharatpur with effect from 5th January, 1970.

(The above note does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory.)

[No. 11(F. No. 261/3/70-ITJ).]

नई दिल्ली, 20 जनवरी 1970

एस. ओ. 2324 :—यात्रा कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करने और इस नियमित अपने को समर्थ चनाने वाली अन्य सभी अधिकारियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष तर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं. 143 (फा. सं. 50/42/69 आई.टी.जे.) तारीख 24-10-69 से उपायद्वारा अनुमूल्यी में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :—

उक्त अनुमूल्यी में—(i) खंड रेज जयपुर के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे अर्डि.नं. उ वार्ड के पश्चात और जयपुर से पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"अतिरिक्त ज-वार्ड"

ii) कोटा रेज, कोटा के सामने, स्तम्भ 2 में मद 2 में भरतपुर मर्किंग के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए अर्थात् :—

"क आर, ख वार्ड, भरतपुर"

यह अधिसूचना 21 जनवरी, 1970 से प्रवृत्त हो जाएगी।

स्पष्टीकारक टिप्पणी :—

यह संशोधन अतिरिक्त—ज-वार्ड, जयपुर और नए बनाए गए वार्ड, ख-वार्ड, भरतपुर पर क्रमसं. 15 विसम्बर, 1969 और 5 जनवरी 1970 से अपीली अधिकारिता में समनुदेशन करने और अप्रयोग कर अधिकारी भरतपुर का क-वार्ड भरतपुर के शाय-कर अधिकारी के रूप में पुनः पदसिधान करने के कारण आवश्यक हो गया है।

(उपरोक्त टिप्पण अधिसूचना का अंश नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकरण के लिए आण्यित है।)

[सं. 11 (फा. सं. 261/3/70-आई.टी.जे.)]

New Delhi, the 20th March 1970

S.O. 2325.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments in the Schedule appended to its Notification No. 12(F. No. 50/7/66-ITJ), dated 14th January, 1966 as amended from time to time, namely—

In the said Schedule against:—

I. 'D'-Range, Calcutta, following shall be substituted—

1. Companies Dist. IV, Calcutta.

('A' to 'F'—Yards only).

After 'X' Range, Calcutta the following shall be added:—

- Companies Dist. IV, Calcutta.
(other than 'A' to 'F'—Wards).

'Y' Range, Calcutta.

This Notification shall take effect from 20th March, 1970.

Explanatory Note

The amendment have become necessary on account of creation of 'Y'-Range, Calcutta, and consequent reallocation of the AACs jurisdiction in West Bengal Charge.

(The above note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory.)

Y. SINGH, Under Secy.

[No. 30(F. No. 261/5/70-ITJ).]

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1970

एस०ओ० 2325 :—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना संख्या 12 (फा० सं० 50/7/66—आई टी जे) तारीख 14 जनवरी, 1966 समय-समय पर यथा संशोधित से संलग्न अनुसूची में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में :—

1. 'घ' रेंज, कलकत्ता के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा —

1 कम्पनी जिला IV, कलकत्ता (केवल वार्ड क से घ तक)

'ग'रेंज, कलकत्ता के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

1 कम्पनी जिला IV, कलकत्ता (क से घ तक वार्ड से भिन्न)।

'म' रेंज, कलकत्ता ।

यह अधिसूचना 20 मार्च, 1970 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण टिप्पण :—

यह संशोधन 'म'-रेंज, कलकत्ता की स्टॉप और परिणामस्वरूप पश्चिमी बंगाल कार्यभार में सहायक आयुक्तों (अपील) की अधिकारिता के पुनरावृत्तन के कारण आवश्यक हुआ है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि उसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है)।

[सं० 30 (फा० सं० 261/5/70—आई टी जे)]

New Delhi, the 21st March 1970

S. O. 2326.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, of the Ranges specified in column (1) of the schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles by the Income-tax Officers specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

SCHEDULE

Range	Income tax Circles and Income-tax Officers.
1	2
1. A A C., A-Range, Bangalore . .	(1) In respect of orders passed under the Income-tax Act by the following Income-tax Officers of Bangalore Circle.— Income-tax Officer (Admn) Income-tax Officer Asst. 1 Income-tax Officer Asst. 2 Income-tax Officer Asst. 3 Income-tax Officer Asst. 8 Income-tax Officer Asst. 9 (2) City Circle I, Bangalore. (3) City Circle III, Bangalore. (4) Kolar Circle. (5) Chitradurga Circle. (6) Spl. Survey Circle, Bangalore. (7) Salary Circle, Bangalore. (8) Tumkur Circle. (9) Circle I, Bangalore. (10) Davangere Circle. (11) Shimoga Circle. (12) Company Circle.
2. A.A.C., B-Range, Bangalore . .	(1) In respect of orders passed under the Income-tax Act by the following Income-tax officers of Bangalore Circle, Bangalore.— Income-tax Officer Asst. 4 Income-tax Officer Asst. 5 Income-tax Officer Asst. 6 Income-tax Officer Asst. 7 Income-tax Officer, Asst. 10 Income-tax Officer Collin. (2) City Circle II, Bangalore. (3) Central Circle, I & II Bangalore. (4) Circle II, Bangalore. (5) Bellary Circle. (6) Raichur Circle.
3. A.A.C., Dharwar Range, Dharawar.	(1) Dharwar Circle. (2) Hubli Circle. (3) Bijapur Circle. (4) Gulbarga Circle. (5) Karwar Circle.
4. A.A.C., Panaji Range, Panaji.	(1) Panaji Circle. (2) Margao Circle. (3) Belgaum Circle.
5. A.A.C., Mysore Range, Mysore.	(1) Mysore Circle. (2) Mangalore Circle. (3) Udupi Circle. (4) Coorg Circle, Mercara. (5) Hassan Circle.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one range to another range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward, District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from where the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification taken effect, be transferred and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st April 1970.

Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of creation of a new Range namely Mysore Range Mysore and consequent reallocation of the AAC's jurisdiction in the Mysore Change.

(This note does not form a part of the notification but is intended to be merely clarificatory.
[No. 31 (F. No. 261/11/70ITJ).]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1970

एस० श्र० 2326 —आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिकात करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट आय-कर सर्किलों में आय-कर अधिकारियों द्वारा आय-कर या अधिकर के लिये निर्धारित सभी शक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेगे :—

अनुसूची

रेज

आय-कर सर्किल और आय-कर अधिकारी

1

2

सहायक आयुक्त (अपील),
क—रेज, बैगलूर

(1) बैगलूर सर्किल के निम्नलिखित आय-कर अधिकारियों द्वारा आय-कर अधिनियम के अधीन पारित आदेशों के बारे में :—

आय-कर अधिकारी प्रशासन
आय-कर अधिकारी निधारण 1
आय-कर अधिकारी निधारण 2
आय-कर अधिकारी निधारण 3
आय-कर अधिकारी निधारण 8
आय-कर अधिकारी निधारण 9

- (2) नगर सर्किल, 1, बैगलूर
- (3) नगर सर्किल, III, बैगलूर
- (4) कोलार सर्किल
- (5) चित्त दुर्गा सर्किल
- (6) विशेष सर्वेक्षण सर्किल, बैगलूर
- (7) वेतन सर्किल, बैगलूर
- (8) टुकुर सर्किल
- (9) सर्किल I, बैगलूर
- (10) दावगूर सर्किल
- (11) शिमोगा सर्किल
- (12) कम्पनी सर्किल

2 सहायक आयुक्त (अपील)
ख-रेज, बैंगलूर

1. बैंगलूर सर्किल, बैंगलूर के निम्नलिखित आय-कर अधिकारियों द्वारा आय-कर अधिनियम के अधीन पारित आदेशों के बारे में :-

आय-कर अधिकारी निर्धारण 4

आय-कर अधिकारी निर्धारण 5

आय-कर अधिकारी निर्धारण 6

आय-कर अधिकारी निर्धारण 7

आय-कर अधिकारी निर्धारण 10

आय-कर अधिकारी वसूली

2. नगर सर्किल II, बैंगलूर

3. के द्वीय सर्किल I और II, बैंगलूर

4. यर्किल II, बैंगलूर

5. बिल्लेरी सर्किल

6. रायचूर सर्किल

1. धारवाड सर्किल

2. हुबली सर्किल

3. बीजापुर सर्किल

4. गुलबर्ग सर्किल

5. कारवाड सर्किल

1. पणजी सर्किल

2. मारगांगो सर्किल

3. बेलगांव सर्किल

1. मैसूर सर्किल

2. मैंगलूर सर्किल

3. उदीपी सर्किल

4. कुर्ग सर्किल, मर्करा

5. हुसन सर्किल

3 सहायक आयुक्त (अपील),
धारवाड रेज, धारवाड

4 सहायक आयुक्त (अपील),
पणजी रेज, पणजी

5 सहायक आयुक्त (अपील),
मैसूर रेज, मैसूर

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेज से दूसरी रेज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेज के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, जिससे वह आय-कर सर्किल या वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेज, के जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएंगी और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही उक्त सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा की जायेंगी ।

यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 1970 से प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकरण टिप्पणी —

यह संशोधन एक नई रेंज अर्थात् मैसूर रेंज, मैसूर की सुष्टि और परिणामस्वरूप मैसूर भारत सभान में सहायक आयुक्तों (अरील) की अधिकारिता के पुनरावंटन के कारण आवश्यक हुआ है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है।)

[सं 31 (फा० सं 261/11/70-आई टी ज)]

New Delhi, the 25th March 1970

S.O. 2327.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof :

SCHEDULE

Range	Income-tax Circle, Wards and Districts.
1	2
Poona Range—I, Poona.	1. B—Ward, Poona. 2. D—Ward, Poona. 3. Addl. D—Ward, Poona. 4. G—Ward, Poona. 5. Addl. G—Ward, Poona. 6. Central Circle, Poona. 7. Wealth-tax Circle, Poona. 8. Special Investigation Circle, Poona. 9. K—Ward, Poona. 10. Collection—I, Poona. 11. Companies Circle, Poona. 12. Addl. Companies Circle, Poona.
Poona Range—II, Poona.	1. A—Ward, Poona. 2. Addl. A—Ward, Poona. 3. C—Ward, Poona. 4. Addl. C—Ward, Poona. 5. E—Ward, Poona. 6. Addl. E—Ward, Poona. 7. F—Ward, Poona. 8. Addl. F—Ward, Poona. 9. H—Ward, Poona. 10. J—Ward, Poona. 11. Addl. J—Ward, Poona. 12. L—Ward, Poona.
Kolhapur Range, Kolhapur.	1. A—Ward, Kolhapur. 2. B—Ward, Kolhapur. 3. C—Ward, Kolhapur. 4. D—Ward, Kolhapur. 5. E—Ward, Kolhapur. 6. F—Ward, Kolhapur. 7. Recovery Circle, Kolhapur. 8. Ratnagiri. 9. A—Ward, Satara. 10. B—Ward, Satara. 11. A—Ward, Sangli. 12. B—Ward, Sangli. 13. C—Ward, Sangli. 14. D—Ward, Sangli.

Nasik Range,
Nasik.

1. A—Ward, Nasik.
2. B—Ward, Nasik.
3. C—Ward, Nasik.
4. D—Ward, Nasik.
5. E—Ward, Nasik.
6. A—Ward, Malegaon.
7. B—Ward, Malegaon.
8. A—Ward, Dhulia.
9. B—Ward, Dhulia.
10. A—Ward, Jalgaon.
11. B—Ward, Jalgaon.
12. C—Ward, Jalgaon.

Sholapur Range,
Sholapur.

1. A—Ward, Sholapur.
2. B—Ward, Sholapur.
3. C—Ward, Sholapur.
4. D—Ward, Sholapur.
5. Special Survey Circle, Poona.
6. Addl. Special Survey Circle, Poona.
7. Salaries and Refund Circle, Poona.
8. GHQ Income-tax Circle, Poona.
9. Collection-II, Poona.
10. A—Ward, Ahmednagar.
11. B—Ward, Ahmednagar.

Akola Range,
Akola.

1. Special Investigation Circle, Akola.
2. A—Ward, Akola.
3. B—Ward, Akola.
4. C—Ward, Akola.
5. Central Circle, Akola.
6. B—Ward, Amravati.
7. D—Ward, Amravati.
8. A—Ward, Yeotmal.
9. B—Ward, Yeotmal.

Amravati Range,
Amravati.

1. A—Ward, Amravati.
2. C—Ward, Amravati.
3. A—Ward, Wardha.
4. B—Ward, Wardha.
5. C—Ward, Wardha.

Aurangabad Range,
Aurangabad.

1. A—Ward, Aurangabad.
2. B—Ward, Aurangabad.
3. C—Ward, Aurangabad.
4. D—Ward, Aurangabad.
5. Latur.
6. A—Ward, Nanded.
7. B—Ward, Nanded.
8. Khamgaon.

Thana Range,
Thana.

1. A—Ward, Thana.
2. Addl. A—Ward, Thana.
3. B—Ward, Thana.
4. C—Ward, Thana.
5. D—Ward, Thana.
6. E—Ward, Thana.
7. F—Ward, Thana.
8. G—Ward, Thana.
9. Special Survey Circle, Thana.
10. Addl. Special Survey Circle, Thana.
11. Recovery Circle—I, Thana.
12. Recovery Circle-II, Thana.
13. Recovery Circle-III, Thana.
14. Palghar.
15. A—Ward, Panvel.
16. B—Ward, Panvel.
17. C—Ward, Panvel.

When an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward, or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st April, 1970.

Explanatory Note

The amendments have become necessary on account of reallocation of work amongst the AACs in the Commissioner's charge and abolition of Jalgaon Range.

(This note does not form a part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).

[No. 34 (F. No. 261/8/70-ITD).]

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1970

एस० ओ० 2327.—ग्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक ग्राय-कर आयुक्त (आपील) उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ग्राय-कर सकिलों वार्डों और जिलों में ग्राय-कर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची

रेज

ग्राय-कर सकिल, वार्ड और जिले

1

2

पूना रेंज-1, पूना

1. ख-वार्ड, पूना
2. घ-वार्ड, पूना
3. अतिरिक्त घ-वार्ड, पूना
4. छ-वार्ड, पूना
5. अतिरिक्त छ-वार्ड, पूना
6. केन्द्रीय सकिल, पूना
7. धन-कर सकिल, पूना
8. विशेष अन्वेषण सकिल, पूना
9. ट-वार्ड, पूना
10. कलवटर-1, पूना
11. कम्पनी सकिल, पूना
12. अतिरिक्त कम्पनी सकिल, पूना

पूनारेंज-2, पूना

1. क-वार्ड, पूना
2. प्रतिरिक्षत क-वार्ड, पूना
3. ग-वार्ड, पूना
4. प्रतिरिक्षत ग-वार्ड, पूना
5. छ.-वार्ड, पूना
6. प्रतिरिक्षत छ.-वार्ड, पूना
7. च-वार्ड, पूना
8. प्रतिरिक्षत च-वार्ड, पूना
9. ज-वार्ड, पूना
10. झ-वार्ड, पूना
11. प्रतिरिक्षत झ-वार्ड, पूना
12. ठ-वार्ड, पूना

कोल्हापुररेंज, कोल्हापुर

1. क-वार्ड, कोल्हापुर
2. ख-वार्ड, कोल्हापुर
3. ग-वार्ड, कोल्हापुर
4. घ-वार्ड, कोल्हापुर
5. छ-वार्ड, कोल्हापुर
6. च-वार्ड, कोल्हापुर
7. वसूली सर्किल, कोल्हापुर
8. रत्नगिरी
9. क-वार्ड, सतारा
10. ख-वार्ड, सतारा
11. ग-वार्ड, सांगली
12. ख-वार्ड, सांगली
13. ग-वार्ड, सांगली
14. घ-वार्ड, सांगली

नासिकरेंज, नासिक

1. क-वार्ड, नासिक
2. ख-वार्ड, नासिक
3. ग-वार्ड, नासिक
4. घ-वार्ड, नासिक
5. छ-वार्ड, नासिक
6. क-वार्ड, मालगांव
7. ख-वार्ड, मालगांव
8. क-वार्ड, घुलिया
9. ख-वार्ड, घुलिया
10. क-वार्ड, जलगांव
11. ख-वार्ड, जलगांव
12. ग-वार्ड, जलगांव

शोलापुररेंज, शोलापुर

- क—वार्ड, शोलापुर
- ख—वार्ड, शोलापुर
- ग—वार्ड, शोलापुर
- घ—वार्ड, शोलापुर
- विशेष सर्वेक्षण संकिल, पूना
- प्रतिरिक्त विशेष सर्वेक्षण संकिल, पूना
- बेतन श्वार प्रतिदाय संकिल, पूना
- जी एच क्यू प्राय-कर संकिल, पूना
- कलक्टर-II, पूना
- क—वार्ड, अहमदनगर
- ख—वार्ड, अहमदनगर

अकोलारेंज, अकोला

- विशेष अन्वेषण संकिल, अकोला
- क—वार्ड, अकोला
- ख—वार्ड, अकोला
- ग—वार्ड, अकोला
- केन्द्रीय संकिल, अकोला
- ख—वार्ड, अमरावती
- घ—वार्ड, अमरावती
- क—वार्ड, यवतमाल
- ख—वार्ड, यवतमाल

अमरावतीरेंज, अमरावती

- क—वार्ड, अमरावती
- ग—वार्ड, अमरावती
- क—वार्ड, वधी
- ख—वार्ड, वधी
- ग—वार्ड, वधी

औरंगाबादरेंज, औरंगाबाद

- क—वार्ड, औरंगाबाद
- ख—वार्ड, औरंगाबाद
- ग—वार्ड, औरंगाबाद
- घ—वार्ड, औरंगाबाद
- लापुर
- क—वार्ड, नान्देड
- ख—वार्ड, नान्देड
- ज्ञाम गांव

थाना रेंज, थाना

1. क-वार्ड, थाना
2. अतिरिक्त क-वार्ड, थाना
3. ख-वार्ड, थाना
4. ग-वार्ड, थाना
5. घ-वार्ड, थाना
6. ङ-वार्ड, थाना
7. च-वार्ड, थाना
8. छ-वार्ड, थाना
9. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, थाना
10. अतिरिक्त विशेष सर्वेक्षण सर्किल, थाना
11. वसूली सर्किल-1, थाना
12. वसूली- सर्किल-2, थाना
13. वसूली सर्किल-3, थाना
14. पालघर
15. क-वार्ड, पानवेल
16. ख-वार्ड, पानवेल
17. ग-वार्ड, पानवेल

जब इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो गया हो तब उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिलेया उसके किसी भाग में निवारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की सारीख से ठीक पहले उस रेंज के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, जिससे वह आय-कर सर्किल या वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की सारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएगी और उनके संबंध में कार्यवाही उक्त सहायक आयुक्त (अपील) द्वारा की जाएगी ।

यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 1970 को प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण टिप्पण :-

ये संशोधन आयुक्त के भारसाधन में सहायक आयुक्तों के (अपील) के बीच कार्यों के पुनराबंटन और जलगांव रेंज के उत्पादन के कारण आवश्यक हुए हैं ।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है ।)

[मं० 34 (फा० सं० 261/8/70-ग्राई टी जे)]

New Delhi, the 30th March, 1970

S.O. 2328.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in supersession of the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Incometax of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Incometax and Super-tax in the Incometax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof.

SCHEDULE

Ranges	Incometax Circles, Ward and District.
I	2
A—Range, Indore.	1. I.T.O. A—Ward, Indore. 2. " C—Ward, Indore. 3. " E—Ward, Indore. 4. " H—Ward, Indore. 5. " P—Ward, Indore. 6. " Q—Ward, Indore. 7. " Special Estate Duty-cum-Incometax Circle, Indore. 8. " Kharone. 9. " Mhow.
B—Range, Indore.	1. " Special Survey Circle, Indore. 2. " Special Inv. Circle, Indore. 3. " Central Circle, Indore. 4. " B—Ward, Indore. 5. " D—Ward, Indore. 6. " F—Ward, Indore. 7. " G—Ward, Indore. 8. " J—Ward, Indore. 9. " K—Ward, Indore. 10. " L—Ward, Indore. 11. " M—Ward, Indore. 12. " N—Ward, Indore. 13. " R—Ward, Indore. 14. Addl. I.T.O. Khandwa. 15. I.T.O. Khandwa. 16. " A—Ward, Khandwa. 17. " B—Ward, Khandwa.
Gwalior Range, Gwalior.	1. " A—Ward, Gwalior. 2. " B—Ward, Gwalior. 3. " C—Ward, Gwalior. 4. " D—Ward, Gwalior. 5. " E—Ward, Gwalior. 6. " F—Ward, Gwalior. 7. " G—Ward, Gwalior. 8. " Guna. 9. " Vidisha.
Bhopal Range, Bhopal.	1. " A—Ward, Bhopal. 2. " B—Ward, Bhopal. 3. " C—Ward, Bhopal. 4. " D—Ward, Bhopal. 5. " E—Ward, Bhopal. 6. " F—Ward, Bhopal. 7. " A—Ward, Ujjain. 8. " B—Ward, Ujjain. 9. " C—Ward, Ujjain. 10. " D—Ward, Ujjain. 11. " E—Ward, Ujjain. 12. " F—Ward, Ujjain. 13. " Betul. 14. " A—Ward, Itarsi. 15. " B—Ward, Itarsi.
Ratlam Range, Ratlam.	1. " A—Ward, Ratlam. 2. " B—Ward, Ratlam. 3. " C—Ward, Ratlam. 4. " A—Ward, Mandsaur. 5. " B—Ward, Mandsaur. 6. " Mandaur. 7. " Dhar.

A—Range, Jabalpur	1. I.T.O. Central Circle, Jabalpur. 2. " A—Ward, Jabalpur. 3. " B—Ward, Jabalpur. 4. " C—Ward, Jabalpur. 5. " A—Ward, Katni. 6. " B—Ward, Katni. 7. " C—Ward, Katni. 8. " A—Ward, Satna. 9. " B—Ward, Satna. 10. " C—Ward, Satna. 11. " D—Ward, Satna. 12. " Special Estate Duty-cum-Income-tax circle, Jabalpur.
B—Range, Jabalpur.	1. " Special Survey Circle, Jabalpur. 2. " C—Ward, Jabalpur. 3. " D—Ward, Jabalpur. 4. " E—Ward, Jabalpur. 5. " F—Ward, Jabalpur. 6. " K—Ward, Jabalpur. 7. " J—Ward, Jabalpur. 8. " Chhindwara. 9. " A—Ward, Chhindwara. 10. " B—Ward, Chhindwara. 11. " A—Ward, Sagar. 12. " B—Ward, Sagar. 13. " C—Ward, Sagar.
Raipur Range, Raipur.	1. " A—Ward, Raipur. 2. " B—Ward, Raipur. 3. " C—Ward, Raipur. 4. " D—Ward, Raipur. 5. " E—Ward, Raipur. 6. " Administration and Collection, Raipur. 7. " Administration, Raipur. 8. " Collection, Raipur. 9. " Assessment—I, Raipur. 10. " Assessment—II, Raipur. 11. " Assessment—III, Raipur. 12. " Assessment—IV, Raipur. 13. " Assessment—V, Raipur. 14. " Assessment—VI, Raipur. 15. " Rajnandgaon. 16. " A—Ward, Rajnandgaon. 17. " B—Ward, Rajnandgaon. 18. " Bilaspur. 19. " A—Ward, Bilaspur. 20. " B—Ward, Bilaspur. 21. " C—Ward, Bilaspur. 22. " A—Ward, Durg. 23. " B—Ward, Durg. 24. " C—Ward, Durg. 25. " Raigarh. 26. " A—Ward, Raigarh. 27. " B—Ward, Raigarh. 28. " Jagdalpur.
Nagpur Range, Nagpur.	1. " A—Ward, Nagpur. 2. " B—Ward, Nagpur. 3. " C—Ward, Nagpur. 4. " D—Ward, Nagpur. 5. " E—Ward, Nagpur. 6. " F—Ward, Nagpur. 7. " G—Ward, Nagpur. 8. " H—Ward, Nagpur.

I.

2.

9.	ITO	Special Survey Circle, Nagpur.
10.	"	City Circle & Refunds, Nagpur.
11.	"	Refund Circle, Nagpur.
12.	"	City Circle, Nagpur.
13.	"	Special Estate Duty-cum-Income tax Circle, Nagpur.
14.	"	Salary Circles, Nagpur. (a) 1st ITO Salary Circle, Nagpur (b) 2nd ITO Salary Circle, Nagpur. (c) 3rd ITO Salary Circle, Nagpur. (d) 2nd ITO Salary Circle & Refunds, Nagpur.
15.	"	Administration, Nagpur.
16.	"	Collection, Nagpur.
17.	"	Assessment—I, Nagpur.
18.	"	Assessment—II, Nagpur.
19.	"	Assessment—III, Nagpur.
20.	"	Assessment—IV, Nagpur.
21.	"	Assessment—V, Nagpur.
22.	"	Assessment—VI, Nagpur.
23.	"	Assessment—VII, Nagpur.
24.	"	Assessment—VIII, Nagpur.
25.	"	Assessment—IX, Nagpur.
26.	"	Assessment—X, Nagpur.
27.	"	Assessment—XI, Nagpur.
28.	"	Assessment—XII, Nagpur.
29.	"	Assessment—XIII, Nagpur.
30.	"	Assessment—XIV, Nagpur.
31.	"	Additional ITO Collection, Nagpur.

Where an Income tax Circle, Ward, or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the AAC of the Range from whom that income tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred, shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the AAC of the Range to whom the said Circle, Ward, or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-4-1970.

Explanatory note.

The amendment has become necessary on account of abolition of one AAC's post at Nagpur and creation of one AAC's post at Jabalpur.

(This note does not form part of the notification, but is interred to be merely clarificatory).

N.C. 41(F. No. 261/6/70-) ITJ.]

नई दिल्ली 30 मार्च, 1970

आयकर

एस० औ० 2328.—आय कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) धारा प्रदल शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीर इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिकृत करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर ओर एतद्वारा निदेश देता है कि मीने की अनूसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रजों के सहायक आय कर

आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय कर सकितों, वार्डों और जिलों में आय कर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने क्रत्यों का पालन करने :—

प्रत्यक्षी

रेंज

आयकर संकिल, वार्ड और जिला

1

2

क—रेंज इंदौर

1. आयकर अधिकारी क—वार्ड, इंदौर
2. " " ग—वार्ड, इंदौर
3. " " ड—वार्ड, इंदौर
4. " " ज—वार्ड, इंदौर
5. " " त—वार्ड, इंदौर
6. " " थ—वार्ड, इंदौर
7. " " विशेष सम्पदा शुल्क एवं आयकर संकिल, इंदौर
8. " " खर्चोन
9. " " महू

ख—रेंज इंदौर

1. " " विशेष सर्वेक्षण संकिल, इंदौर
2. " " विशेष अम्बेषण संकिल, इंदौर
3. " " केन्द्रीय संकिल, इंदौर
4. " " ख—वार्ड, इंदौर
5. " " थ—वार्ड, इंदौर
6. " " च—वार्ड, इंदौर
7. " " छ—वार्ड, इंदौर
8. " " झ—वार्ड, इंदौर
9. " " ट—वार्ड, इंदौर
10. " " ठ—वार्ड, इंदौर
11. " " ड—वार्ड, इंदौर
12. " " ठ—वार्ड, इंदौर
13. " " द—वार्ड, इंदौर
14. अपर आयकर अधिकारी, खंडवा
15. आयकर अधिकारी खंडवा
16. " " क—वार्ड, खंडवा
17. " " ख—वार्ड, खंडवा

बालियर रेज ग्वालियर

1. श्राव्य-कर ग्वालियरी क—वार्ड, ग्वालियर
2. " " ख—वार्ड, ग्वालियर
3. " " ग—वार्ड, ग्वालियर
4. " " घ—वार्ड, ग्वालियर
5. " " ड—वार्ड, ग्वालियर
6. " " च—वार्ड, ग्वालियर
7. " " छ—वार्ड, ग्वालियर
8. " " गुना
9. " " विदिशा

भोपाल रेज- भोपाल

1. " " क—वार्ड, भोपाल
2. " " ख—वार्ड, भोपाल
3. " " ग—वार्ड, भोपाल
4. " " घ—वार्ड, भोपाल
5. " " ड—वार्ड, भोपाल
6. " " च—वार्ड, भोपाल
7. " " क—वार्ड, उज्जैन
8. " " ख—वार्ड, उज्जैन
9. " " ग—वार्ड, उज्जैन
10. " " घ—वार्ड, उज्जैन
11. " " ड—वार्ड, उज्जैन
12. " " च—वार्ड, उज्जैन
13. " " बेतुल
14. " " क—वार्ड, इटारसी
15. " " ख—वार्ड, इटारसी

रतलाम रेज- रतलाम

1. " " क—वार्ड, रतलाम
2. " " ख—वार्ड, रतलाम
3. " " ग—वार्ड, रतलाम
4. " " क—वार्ड, मंवसीर
5. " " ख—वार्ड, मंवसीर
6. " " मंवसीर
7. " " शाय

क—रेज जबलपुर

1. " " केन्द्रीय सर्किल, जबलपुर
2. " " क—वार्ड, जबलपुर
3. " " ख—वार्ड, जबलपुर
4. " " छ—वार्ड, जबलपुर
5. " " क—वार्ड, कटनी
6. " " ख—वार्ड, कटनी

7.	आथ-कर प्रशिकारी ग-वार्ड, कटनी
8.	“ “ क-वार्ड, सतना
9.	“ “ ख-वार्ड, सतना
10.	“ “ ग-वार्ड, सतना
11.	“ “ घ-वार्ड, सतना
12.	“ “ विशेष सम्पदाशुल्क एवं आयकर सर्किल, जबलपुर
जब-रेज जबलपुर	1. “ “ विशेष सर्वेक्षण सर्किल, जबलपुर
	2. “ “ ग-वार्ड, जबलपुर
	3. “ “ घ-वार्ड, जबलपुर
	4. “ “ ङ-वार्ड, जबलपुर
	5. “ “ च-वार्ड, जबलपुर
	6. “ “ ज-वार्ड जबलपुर
	7. “ “ छ-वार्ड जबलपुर
	8. “ “ छिन्दवाड़ा
	9. “ “ क-वार्ड छिन्दवाड़ा
	10. “ “ ख-वार्ड छिन्दवाड़ा
	11. “ “ क-वार्ड सागर
	12. “ “ ख-वार्ड सागर
	13. “ “ ग-वार्ड सागर
आयपुर रेज रायपुर	1. “ “ क-वार्ड रायपुर
	2. “ “ ख-वार्ड रायपुर
	3. “ “ ग-वार्ड रायपुर
	4. “ “ घ-वार्ड रायपुर
	5. “ “ अ-वार्ड रायपुर
	6. “ “ प्रशासन और वसूली, रायपुर
	7. “ “ प्रशासन रायपुर
	8. “ “ वसूली रायपुर
	9. “ “ निर्धारण I रायपुर
	10. “ “ निर्धारण II रायपुर
	11. “ “ III रायपुर
	12. “ “ निर्धारण IV रायपुर
	13. “ “ निर्धारण V रायपुर
	14. “ “ निर्धारण VI रायपुर
	15. “ “ राजनन्दगाव

16. आयकर अधिकारी क-वार्ड राजनाडगांव
 17. ख-वार्ड राजनाडगांव
 18. विलासपुर
 19. क-वार्ड विलासपुर
 20. ख-वार्ड विलासपुर
 21. ग-वार्ड विलासपुर
 22. क-वार्ड दुर्ग
 23. ख-वार्ड दुर्ग
 24. ग-वार्ड दुर्ग
 25. रायगढ़
 26. क-वार्ड रायगढ़
 27. ख-वार्ड रायगढ़
 28. जगदलपुर

नागपुर रेज, नागपुर

1. आयकर अधिकारी क-वार्ड नागपुर
 2. ख-वार्ड नागपुर
 3. ग-वार्ड नागपुर
 4. घ-वार्ड नागपुर
 5. य-वार्ड नागपुर
 6. च-वार्ड नागपुर
 7. छ-वार्ड नागपुर
 8. ज-वार्ड नागपुर
 9. विशेष सर्वेक्षण सर्किल,
 नागपुर
 10. नगर सर्किल और प्रतिवाय,
 नागपुर
 11. प्रतिवाय सर्किल, नागपुर
 12. नगर सर्किल, नागपुर
 13. विशेष सम्पाद शुल्क एवं
 आयकर सर्किल, नागपुर
 14. वेतन सर्किल, नागपुर
 (क) प्रथम सर्किल आयकर अधिकारी वेतन सर्किल,
 नागपुर ।
 (ख) द्वितीय आयकर अधिकारी वेतन सर्किल,
 नागपुर ।
 (ग) तृतीय आयकर अधिकारी वेतन सर्किल,
 नागपुर ।
 (घ) द्वितीय आयकर अधिकारी वेतन सर्किल और
 प्रतिवाय, नागपुर ।

15. आयकर अधिकारी प्रशासन, नागपुर।
 16. वसूली, नागपुर
 17. निधारण I, नागपुर
 18. निधारण II, नागपुर
 19. निधारण III, नागपुर
 20. निधारण IV, नागपुर
 21. निधारण V, नागपुर
 22. निधारण VI, नागपुर
 23. निधारण VII, नागपुर
 24. निधारण VIII, नागपुर
 25. निधारण IX, नागपुर
 26. निधारण X, नागपुर
 27. निधारण XI, नागपुर
 28. निधारण XII, नागपुर
 29. निधारण XIII, नागपुर
 30. निधारण XIV नागपुर
 31. अपर आयकर अधिकारी वसूली नागपुर।

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय कर सकिल, वार्ड, या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आयकर सकिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में निधारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, जिस से वह आय कर सकिल या वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर वी जाएगी और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही उक्त सहायक आयुक्त (अपील) द्वारा की जाएगी।

यह अधिसूचना 1-4-1970 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पणी :

यह संशोधन नागपुर में एक सहायक आयुक्त (अपील) के पद के उत्पादन और जबलपुर में एक अपीली सहायक आयुक्त (अपील) के पद की सूचित के कारण आवश्यक दुश्मा है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि उसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है)।

[सं. 41 (फा. सं. 261/6/70-आई. टी. जे.)]

New Delhi, the 31st March 1970

S.O. 2329.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes makes the following amendments in the Schedule appended to its notification No. 143(F. No. 50/42/69-ITJ), dated 24th October, 1969 viz.—

In the said Schedule against the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bikaner under Column 2 the following shall be substituted:—

1. All Income-tax Wards having headquarters at Bikaner.
2. All Income-tax Wards, Circles having headquarters at Sriganganagar.

In the said Schedule against the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Kota under Column-2 the following shall be substituted:—

1. All Income-tax Wards/Circles having headquarters at Kota.
2. Bharatpur Circle.
3. Swaimadhopur Circle.

This notification shall take effect from the 1st April, 1970.

Explanatory Note

The amendment has become necessary for assigning appellate jurisdiction over Special Survey Circles, Kota and Sriganganagar newly created Circles R.F.P. 31st March, 1970 (A.N.).

(The above note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 42(F. No. 261/3/70-ITJ).]
Y. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली 31, मार्च, 1970

एस. नं. 2329.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की द्वारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना सं. 143 (फा. सं. 50/42/69-आई.टी.जे) तारीख 24-10-69 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में सहायक आय कर आयुवन (आपील) बीकानेर, के मामले स्तम्भ 2 के नीचे निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

1. सभी आयकर वार्ड जिनका मुख्यालय बीकानेर में है।
2. सभी आयकर वार्ड, सर्किल जिनका मुख्यालय श्रीगंगानगर में है।

उक्त अनुसूची में सहायक आय कर आयुवन (आपील) कोटा के मामले स्तम्भ 2 के नीचे निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

1. सभी आय कर वार्ड/सर्किल जिनका मुख्यालय कोटा में है।
2. भरतपुर सर्किल।
3. सवाईमाधोपुर सर्किल।

यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 1970 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण दिप्पण :—

यह संशोधन 31 मार्च, 1970 (अप्राह्ण) से नवसृष्ट राकिलों, विशेष सर्वेक्षण सर्किल, कोटा और श्रीगंगानगर पर अपीली अधिकारिता सौंपने के लिए आवश्यक हुआ है।

(उपर्युक्त दिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि उसका आशय स्पष्टीकरण, मार्द है)।

[सं. 42 (फा. सं. 261/3/70-ग्राइ.टी.जे.)]
वाई. मित्र, प्रबंध सचिव।

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

CUSTOMS

New Delhi, the 11th July 1970

S.O. 2330.—In pursuance of sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby directs that Shri M.

Ramachandran, Collector of Customs, Bombay, shall not, as such Collector, exercise any powers or discharge any duties conferred or imposed on a Collector of Customs under the said Act other than those under Chapter XIV thereof.

[No. 68/F. No. 22/5/70-Cus.IV.]

J. DATTA, Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1970

एस० नं० 2330.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उपधारा (1) अनुसरण करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड एतदशारा निवेश देता है कि श्री एस० रामचन्द्रन, सीमा शुल्क कालकटर, मुम्बई, ऐसे कालकटर के रूप में, उक्त अधिनियम के ध्याय 14 के अधीन सीमा शुल्क कालकटर को प्रदत्त शक्तियों या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों से भिन्न किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों का निवृहन नहीं करेंगे।

[संख्या 68/फा० स० 22/5/70—सीमा शुल्क—4]

ज्योतिर्मय दत्त, सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd July 1970

S.O. 2331.—In para 2, lines 5 of the Order No. S.O. I, dated the 23rd April, 1970;

For "President" read "Member, Managing Committee".

[No. 2-49/68-MEI.]

By Order,

R. SUBRAMANIAN, Under Secy.

श्रीदोषिन वित्तस, आरटिन इगापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(श्रीदोषिन वित्तस विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1970

एस० नं० 2331.—आदेश संख्या एस० नं० 1 विनांक 23-4-70 की पंक्ति 5 पैरा 2 में :—

"अध्यक्ष" के स्थान पर

"मदस्य प्रबन्धक समिति" पढ़िये।

[स० 2-49/68-एमइआई]

आदेशानुसार,

आर० सुनामनियन, प्रवर सचिव।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 17th June 1970

S.O. 2332.—In exercise of the powers conferred by Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely—

(a) These rules may be called the Indian Post Office (Fifth Amendment) Rules, 1970.
(b) They shall come into force at once.

2. In rule 188 of the Indian Post Office Rules, 1933, the last sentence starting with the words "Service stampys" and ending with the words "foreign countries" shall be omitted.

[No. 39/4/70-CN.]

K. GOPALAKRISHNAN,

Deputy Director-General (Mails).

संचार विभाग

(डाक-सार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 जून, 1970

एस० ओ० 2332.—भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 (1898 का 6) की धारा 74 के द्वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर नियमावली 1933 में और आगे मंशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्यात्:

(क) ये नियम भारतीय डाक गर (पांचवां मंशोधन) नियमावली, 1970 कहलायेंगे।
(ख) ये नियम तत्काल से ही लागू होंगे।

2. भारतीय नियमावली, 1933 के नियम 188 में "सेवा टिकट" शब्दों से शुरू होने वाले और "विदेश" शब्द से खत्म होने वाले अनिम वाक्य को हटा दिया जाय।

[म० 39-4/70-सी०एन०]

कै० गोपालकृष्णन,

उप-महानिदेशक (डाक)।

(P. & T. Board)

New Delhi, the 1st July 1970

S.O. 2333.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 424 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director-General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16th July, 1970 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in KALYAN and local exchange system comprising of Kalyan, Ulhasnagar, Ambarnath and Dombivili exchanges, Maharashtra Circle.

[No. 5-47/70-PHB.]

HARIKISHAN SINGH,
Assistant Director General (PHB).

आनंद बोर्ड

नई दिल्ली, 1 जूलाई, 1970

एस० अ० 2333—स्थायी आदेश क्रम संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए 1951 के भारतीय तार नियमों के नियम 434 के खण्ड III के दैरा (क) के अनुमार डाक-तार महानिदेशक ने महाराष्ट्र सर्कल के कल्याण स्थानीय एक्सचेंज प्रणाली में जिसमें कल्याण, उल्हास नगर, अम्बरनाथ और डोम्बीविली एक्सचेंज शामिल है, ता० 16 जूलाई, 1970 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[स० 5-47/70-प० एच० बी०]

हरकिशन मिह,

सहायक महानिदेशक (प० एच० बी०)।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RUBBER CONTROL

New Delhi, the 19th June 1970

S.O. 2334.—In pursuance of clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the Central Government hereby notifies that Shri S. Kumaran, Member of Rajya Sabha, House No. 941, Thampanur, Trivandrum (Kerala), has been elected by the Rajya Sabha as a member of the Rubber Board, Kottayam, for a period of 3 years with effect from the 19th June, 1970, or for so long as he continues to be a Member of the Rajya Sabha, whichever is less.

[No. F. 15(4) Plant(B)/70.]

M. L. GUPTA, Under Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

(रबड़ नियंत्रण)

नई दिल्ली, 19 जून, 1970

ए० अ० 2334.—रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) के उप-खण्ड 4 के उप-खण्ड (3) की धारा (इ) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सूचित करती है कि राज्य सभा के सदस्य श्री एस० कुमारन, मकान नं० 941, थम्पानूर, त्रिवेन्द्रम (केरल), 19 जून, 1970 से तीन वर्ष की अवधि के लिये या जब तक वह राज्य सभा के सदस्य बने रहें, जो भी कम हो, राज्य सभा द्वारा रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के सदस्य चुने गये हैं।

[स० का० 15(4) प्ल०ट (बी०) /70]

एम० एल० गुप्ता, अव०र सचिव।

CARDAMOM CONTROL

New Delhi, the 27th June 1970

S.O. 2335.—In supersession of this Ministry's notification No. S.O. 1813 published in the Gazette of India in part II Section 3 Sub-Section (ii) dated the 23rd May, 1970, Shri K. V. George, Director of Cardamom Development, Cardamom Board, Ernakulam is granted leave for sixty days with effect from the 8th April, 1970 with permission to suffix the holiday on Sunday, the 7th June, 1970 to his leave.

[No. F.29(36)Plant(B)/70.]

M. L. GUPTA, Under Secy.

इलायची नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 जून, 1970

एस० अ० २३३५.—भारत के राजपत्र भाग २ खण्ड ३ उप-खण्ड (२) में दिनांक २३ मई, १९७० को प्रकाशित इस मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० अ० १८१३ का अधिक्रमण करते हुए, इलायची बोर्ड एनाकुलम में इलायची विकास के निदेशक, थी के० वी० जार्ज को ८ अप्रैल, १९७० से साठ दिन की छुट्टी मजूर की जाती है और उन्हें इस छुट्टी के साथ ७ जून १९७० की रविवार की छुट्टी जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है।

[२९(३६)-प्लांट(बी)/७०]

एम० एल० गुप्ता, अध्यक्ष सचिव।

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING & W.H. & U.D.

(Department of Health)

New Delhi, the 27th June 1970

S.O. 2336.—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is published, as required by the said sections for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 25th August, 1970.

2. Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 1970.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule K, in entry 10(ii), in the first column "Class of Drugs", the word 'Lactose', shall be omitted.

[No. 1-50/70-D.]

L. K. MURTHY, Under Secy.

(Department of Health)

New Delhi, the 1st July 1970

S.O. 2337.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the Schedule to the said Act the names of the following public Institution, namely:—

"The Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh."

[No. F.1-54/69-ME(PG)Pt.II.]

स्वास्थ्य, परिवार विधोजन, निर्माण, अवास एवं नगर विभास भवान्य

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1970

एस० अ० २३३७.—भविष्य निधि अधिनियम, १९२५ (१९२५ का १९) की धारा ४ की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित सार्वजनिक संस्था को सम्मिलित करती है, नामशः

"स्नातकोत्तर चिकित्सा-शिक्षा एवं अनुमधान संस्थान, चंडीगढ़"।

[मं० एफ० १-५४/६९-एम० ई० (पी० जी०) अ३-२]

S.O. 2338.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh.

[No. F.1-54/69-ME(PG)Pt.II.]

M. C. MISRA, Dy. Secy.

एस० ओ० 2338.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एनदब्ल्यूआर निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध स्तरात्मकतर विकित्ता शिक्षा एवं अनुप्रान संस्थान चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लाभार्थ स्थापित भविष्य निधि पर भी लागू होंगे।

[स० एफ० 1-54/69-एस० ई० (फी० जी०) खंड-2]

महेश चन्द मिश्र, उप-मंत्री।

(Department of Works, Housing and Urban Development)

New Delhi, the 3rd July 1970

S.O. 2339.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958 (32 of 1958), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the table below being gazetted officer of Government, to be estate officer for the purpose of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers, by or under, the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said table.

THE TABLE

Designation of officer (1)	Categories of public premises and local limits of jurisdiction. (2)
Senior law Officer, Directorate General of Mines Safety, Dhanbad.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by and under on behalf of the Central Government and under the administrative control of the Director General of Mine safety at Dhanbad in Bihar and at Sitarampur in West Bengal.

[No. F. 21011(4)/66-Pol.IV.]

(दिर्माण, आवास और नगर विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2339.—लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 (1958 का 32) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गयी सारणी के आधारे (1) में उल्लिखित अधिकारी को सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते एतद-द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के आधारे (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट लोक परिसरों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन, सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सरसो

अधिकारी का पदनाम

लोक परिसर का वर्ग और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं

(1)

(2)

वरिष्ठ विधि अधिकारी, महानिदेशालय, धनबाद (बिहार) में और सीतारामपुर (पश्चिमी बंगाल) में महानिदेशक, खान, संरक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके द्वारा, और उसको और से पट्टे पर लिये गये या अधिग्रहीत परिसर ।

[सं. फा. 21011 (4)/66-नीति-4]

S.O. 2340.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958 (Central Act No. 32 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Works, Housing and Supply (Department of Works and Housing) No. S.O. 3911, dated the 17th September, 1969, namely:—

In the table appended to the said notification for the entry in column (1), the following entry shall be substituted, namely:—

“Hospital Engineer-cum-Estate Officer, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh.”

[No. F. 21011(4)/66-Pol. IV.]

एस० ओ० 2340:—लोक परिसर (अनिवार्य दबालकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 32) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवंद्वारा भारत सरकार के निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय, (निर्माण और आवास विभाग), की तारीख 17 सितम्बर, 1969 की अधिसूचना सं० एस० ओ० 3911 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में खाना (1) में दी गयी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी, नामश:—

“हास्पीटल इंजीनियर व सम्पदा अधिकारी, पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मैडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ ।”

[सं. फा. 21011 (4)/66-नीति (4)]

S.O. 2341.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958 (32 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development) No. S.O. 4194 dated the 7th October, 1969, namely:—

In the table to the said notification in column (2) against serial No. 1, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“Premises belonging to or under the administrative control of, or taken on lease by Hindustan Steel Limited situated in the District of Ranchi, Bihar.”

[No. F. 21011(4)/66-Pol.IV]

एस० औ० 2341:—लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 (1958 का 32) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग), की तारीख 7 अक्टूबर, 1969 की अधिसूचना सं० एस० औ० 4194 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में ऋम सं० 1 के सामने खाना (2) में दी गयी प्रविष्टि के लिये निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी ।

“जिला रांची, बिहार में स्थित, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के स्वामित्व, में या उनके प्रशासनिक नियन्त्रण में या उनके द्वारा पट्टे पर लिये गये परिसर” ।

[सं० फा० 21011 (4)/66-नीति- (4)]

S.O. 2342.—In exercise of the powers conferred by section 3 of Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958 (32 of 1958), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officer of Government to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Designation of officers	Categories of public premises and local limits of jurisdictions.
(1)	(2)
Assistant Shipping Master, Marine House, Hostings, Calcutta.	Public premises belonging to the Central Government situated at 1/4, Stand Road, Calcutta-within the Municipal limits of Calcutta corporation.

[No. F. 21011(4)/66-Pol.IV.]

एस० औ० 2342:—लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 (1958 का 32) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के खाना (1) में उल्लिखित अधिकारी को, सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के कारण, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के खाना (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट लोक परिसरों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का नाम	लोक परिसर का वर्ग और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
सहायक जहाजरानी मास्टर, मैरिन हाउस, हेस्टिंग, कलकत्ता	कलकत्ता नगर निगम की नगर सीमाओं के भीतर 1/4 स्ट्रेड रोड, कलकत्ता पर स्थित, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में लोक परिसर ।

[सं० फा० 21011(4)/66-नीति-4]

S.O. 2343.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958 (32 of 1958), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the table below, being gazetted officer of Government to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said table.

THE TABLE

Designation of officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Executive Engineer,, Hyderabad Central Divisional No. 1 C.P.W.D. Hyderabad.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Central Government at Hyderabad as are under his administrative control.

[No. F. 21011(4)/66-Pol.IV.]

एस० फो० 2343:—लोक परिसर (ग्रन्थिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 (1958 का 32) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के खाना (1) में उल्लिखित अधिकारी को सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के कारण एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के खाना (2) में पदनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट लोक परिसरों के सम्बन्ध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारियों की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उनपर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	लोक परिसर का वर्ग और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
कार्यपालक इंजीनियर, हैदराबाद सेंट्रल इंजीनियरिंग नं० 1, कॉ० लो० नि० वि० हैदराबाद	हैदराबाद में केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या पट्टे पर लिए गए या उस द्वारा या उसकी ओर से अधिगृहीत परिसर, जो कि उनके प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन हों।

[सं० फा० 21011 (4)/66-नीति-4.]

S.O. 2344.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958 (32 of 1958), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the table below, being gazetted officers of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers, by or under, the said Act, within the local limits

of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said table.

THE TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limit of jurisdiction.
(1)	(2)
(1) (i) Divisional Engineer I, Samastipur, North Eastern Railway.	Premises under the administrative control of the North Eastern Railway situated within the jurisdiction of Samastipur Division.
(ii) Engineer-in-Chiefs, North Eastern Railway.	Premises under the administrative control of North Eastern Railway.
(2) Divisional Superintending Engineers, Delhi and Allahabad Divisions.	Premises under the administrative control of the Northern Railway situated within the jurisdiction of Delhi and Allahabad Divisions.
(3) (i) Divisional Superintendent, Lumding, North East Frontier Railway.	Premises under the administrative control of North East Frontier Railway situated within the jurisdiction of Divisional Superintendent Lumding, except Gauhati, Pandu and Amingaon.
(ii) Estate Officer, (Full Time) North East Frontier Railway.	Premises under the administrative control of North East Frontier Railway situated within the jurisdiction of Gauhati, Pandu and Amingaon areas.
(iii) Divisional Superintendents Alipurduar Junction and Kathiawar.	Premises under the administrative control of North East Frontier Railway situated within the jurisdiction of Divisional Superintendents of Alipurduar Junction.
(4) (i) Deputy Divisional Superintendent, Bombay.	Premises under the administrative control of Central Railways situated within their respective jurisdictions.
(ii) Divisional Superintending Engineers, Bhusawal and Jhansi Divisions.	
(5) Senior Deputy General Manager, North East Frontier Railway	Premises under the administrative control of the North East Frontier Railway situated within the jurisdiction of Gauhati, Pandu, Amingaon and Maligaon areas.

[No. F. 21011(4)/66-Pol.IV.]

T. K. BALASUBRAMANIAN,
Dy. Director of Estates and
Ex. Officio Under Secy.

एस० ओ० 2344:—लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 (1958 का 32) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गयी सारणी के खाना (1) में उल्लिखित अधिकारियों को सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त

शारणी के खाना (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट लोक परिसरों के सम्बन्ध में अपने अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करेंगे और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम

लोक परिसर का वर्ग और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं

(1)

(2)

1. (i) मंडल इंजीनियर-1, समस्तीपुर, उत्तर पूर्वीय रेलवे। समस्तीपुर मंडल के क्षेत्राधिकार में स्थित, उत्तर पूर्वीय रेलवे के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन परिसर।
(ii) प्रमुख इंजीनियर, उत्तर रेलवे पूर्वीय उत्तर पूर्वीय रेलवे के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन परिसर।
2. मंडल-अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली और इलाहाबाद मंडलों के क्षेत्राधिकार में स्थित, उत्तरीय रेलवे के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन परिसर।
3. (i) मंडल अधीक्षक, लुम्डिनग उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे। मंडल-अधीक्षक, लुम्डिनग के क्षेत्राधिकार में स्थित (गोहाटी, पाढ़ु और अमीनगांवों को छोड़कर), उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन परिसर।
(ii) सम्पदा अधिकारी (पूर्ण कालिक) उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे। गोहाटी, पाढ़ु और अमीनगांवों क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में स्थित उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन परिसर।
(iii) मंडल अधीक्षक, अलीपुरद्वार जंकशन और कटिहार। अलीपुरद्वार जंकशन के मंडल अधीक्षकों के क्षेत्राधिकार में स्थित, उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन परिसर।
4. (i) उप मंडल अधीक्षक, बम्बई। अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्थित, केन्द्रीय रेलवे के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन परिसर।
(ii) मंडल अधीक्षक, इंजीनियर, भुसवाल और आंसी मंडल।
5. वरिष्ट उप महा प्रबन्धक, उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे। गोहाटी, पाढ़ु अमीनगांवों और भालीगांवों क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में स्थित उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन परिसर।

[सं० फा० 21011(4)/66-नीति-4]

टी० क० बालसुत्रमणियन,
उप सम्पदा निवेशक तथा पदेन,
मवर सचिव।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION
(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 27th June 1970

S.O. 2345.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4895 dated the 1st December, 1969, the banking industry carried on by a banking company as defined in clause (bb) of section 2 of the said Act, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 29th December, 1969;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 29th June, 1970.

[No. F.1/36/70-L.R.I.]

भ्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(भ्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 1970

का० आ० 2345 :—यतः केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में एसा अपेक्षित है, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (छ) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (भ्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 4895 तारीख प्रथम दिसम्बर, 1969 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (खख) में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी द्वारा खलाए जा रहे बैंककारी उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर, 1969 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा धोषित किया था ;

श्री यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि का छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (छ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 जून, 1970 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा धोषित करती है ।

[का० सं० 1/36/70 एल० आर० II]

New Delhi, the 1st July 1970

S.O. 2346.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Rajasthan and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th June, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR.
PRESENT:

Shri Gopal Narain Sharma, *Presiding Officer.*

CASE NO. CIT-20 OF 1969.

Ref.—Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), New Delhi Order No. 23/ 86/69/LRIII dated 12th September, 1969.

In the Matter of an Industrial Dispute.

BETWEEN

The Rajasthan (State) Bank Workers Organisation, Ajmer.

AND

The Bank of Rajasthan, Johri Bazar, Jaipur.

Date of Award: 25th May, 1970.

AWARD

The Central Government by its order dated 12th September, 1969 referred the following dispute between the employers in relation to the Bank of Rajasthan and their workmen to this Tribunal for adjudication:—

“Whether Shri Mishrilal Agarwal formerly a workman of the Bhilwara branch of the Bank of Rajasthan, Johri Bazar, Jaipur is entitled to permanent absorption in the employment of the bank and if so, from what date?”

During the pendency of proceedings the parties mutually settled the dispute out of Court in the following terms and prayed for passing an award in terms of the settlement:—

(1) That the opposite party Bank will appoint Shri Mishri Lal as Clerk-cum-Godown keeper on probation for six months on an initial salary of Rs. 122/- and other allowance as per rules in force as a very special case without creating any precedent.

(2) He will be offered appointment within a fortnight period from today.

The settlement appears to be reasonable and fair. Hence an award in terms of the settlement mentioned above is passed accordingly. It may be submitted to the Central Government for publication.

GOPAL NARAIN SHARMA,

Presiding Officer,

Central Government Industrial Tribunal,
Rajasthan, Jaipur.

[No. 23/86/69/LRIII.]

S.O. 2347.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the Chartered Bank, Kanpur and their workmen represented by the U.P. Bank Employees Union, Kanpur which was received by the Central Government on the 26th June, 1970.

In the matter of arbitration in an Industrial Dispute between the management of the Chartered Bank and their workmen represented by U.P. Bank Employees Union, Kanpur over alleged non-payment of special assistant allowance to Shri Mahendra Nath Nigam from 22-12-1968 and not to change his designation from clerk to special assistant.

PRESENT:

Shri V. P. Gupta, Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur.
Arbitrator.

Representing the management:

Shri A. K. Kakkar, Officer of Chartered Bank, Kanpur.

Representing the workmen:

- (1) Shri Harmangal Prasad, Secretary, U.P. Bank Employees' Union, Kanpur.
- (2) Shri M. N. Nigam, the workman.

AWARD

1. By a written agreement dated 27th October 1969 before the Assistant Labour Commissioner (Central), Kanpur the representative of the employer (Management) and the representatives of the workman (Union) agreed to refer for arbitration by me under the provisions of Section 10-A of the I. D. Act, 1947, the following specific matter in dispute between them:—

“Whether the management of the Chartered Bank Kanpur is justified in non-payment of Special Assistant Allowance of Rs. 75 per month to Shri Mahendra Nath Nigam of the Chartered Bank Kanpur from 22nd December 1968 and not to change his designation from clerk to Special Assistant? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. The parties further agreed that the decision of the Arbitrator shall be binding on them. It was also provided that the Arbitrator shall make his award within a period of 31st March, 1970 or within such further time as may be extended by mutual agreement between the parties in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and the parties shall be free to negotiate for fresh arbitration.

3. The said written agreement dated 27th October 1969 was published by the Central Government in pursuance of the provisions of sub-section (3) of Section 10-A of the I.D. Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) Notification No. S.O.—4702 dated 12th November 1969 in the Gazette of India dated 22nd November 1969 Part II—Section 3 sub-section (ii)—P. 5140-41.

4. The parties were called upon to file their written statements on the points in dispute vide my order dated 9th December, 1969 by 25th December, 1969. They were also advised to endorse simultaneously a copy of their written statement to the opposite party who were required to furnish their counter-comments thereon so as to reach the undersigned by 5th January, 1970. While the management filed their written statement vide their letter dt. 18th December, 1969, the Union vide their letter dt. 23rd December, 1969 requested for extension of the date for submission of the statement of their claim upto 10th January, 1970. The request was granted. The statement of the union was received on 12th January, 1970. The counter-comments of the management were received in my office on 21st January, 1970 and those of the union on 27th January, 1970. A hearing in the matter was fixed for 18th February, 1970. Since the date was not convenient to the union a request on their behalf was received on 7th February, 1970 for postponement of the date and accordingly the next hearing was fixed for 4th March, 1970. The workman's representative again asked for adjournment to any date after 15th March, 1970 as he had been invited to Calcutta for participation in the adjourned negotiations between the management and the Chartered Bank Organisation Employees' Federation. The next date was accordingly fixed for 20th March, 1970. On the appointed date the parties agreed that the time allowed to the Arbitrator to give his award by 31st March, 1970 be extended up to 31st May, 1970. They also prayed that they may be allowed to discuss the matter mutually up to 30th April, 1970 and in case nothing is heard from the parties in this regard by that date the Arbitrator may take up the dispute for his arbitration. The request of the parties was granted and they were allowed to have mutual discussions and report the result to the undersigned. The management vide their letter dt. 1st May, 1970 intimated that a meeting was held with the union on 29th March, 1970 and the management had communicated with their Chief Manager and they would advise the Arbitrator as soon as they hear from the Chief Manager. The management vide their letter dated 20th May, 1970 informed the Arbitrator that the Chief Manager in Calcutta had expressed his inability to agree to the terms put forward by the union. The management requested the Arbitrator to take up the dispute for arbitration. The parties were addressed by me vide my letter dated 22nd May, 1970 stating that the time allowed for making the award (till 31st May, 1970) was too little and it appeared extremely difficult, if not impossible, to make the award by that date. The parties were required to intimate the Arbitrator jointly by 31st May, 1970 whether the above said period was further to be extended till 30th June, 1970. It was also added that in case nothing is heard by the Arbitrator by 31st May, 1970, he would presume that the arbitration stands cancelled. The parties vide their letter No. 1468 M/Mise dt. 27th May, 1970 signed jointly extended the period for the award till 30th June, 1970. A hearing in the matter was fixed for 12th June, 1970. The same was resumed on 18th June, 1970.

5. In the written statement the management has listed out the duties which may be allotted to Special Assistants so as to qualify for special allowance. It was stated that vide a Memorandum of Settlement between the Chartered Bank

Organisation Employees Federation and the management on 28th March 1968 it had been agreed that Special Assistants shall perform any or all the duties prescribed for them under the Bi-partite Settlement as and when called upon, from time to time, so to do by the management in addition to their routine clerical duties and functions. The management's case was that at no time did they allot any of the duties cited earlier to Shri M. N. Nigam nor to their knowledge did he perform any of them Shri M. N. Nigam has simply assisted a Special Assistant in routine clerical duties and that was an insufficient reason to qualify for the allowance. The allowance was paid at Kanpur or any other branch of the bank for performing the listed duties which are in addition to the normal routine clerical duties. It was also added that despite their requests Shri Nigam had not informed them of the exact nature of the special duties which he alleged to have performed. Regarding the change of designation of Shri Nigam, who, it was stated, was approximately 24th in the order of seniority, it was added, that the question did not arise. In the management's considered opinion he does not possess the seniority, ability or the qualifications for consideration of his promotion. Additionally, on 18th August, 1969 the U.P. Bank Employees Union had submitted a formula acceptable to them governing future promotions in this category, under the terms of which Shri Nigam would be automatically disqualified. The management's acceptance or otherwise of this formula, it was added, was pending because they had not heard from their Chief Manager in India to whom the issue had been referred.

6. The U.P. Bank Employees' Union, on the other hand, stated that Shri Nigam, who was appointed on 1st November 49 was a bonafide member of the union and he was required to serve on the Accounts table from 22nd December 1968. The Accounts table was under the permanent charge of Shri R. S. Srivastava, who was a permanent Special Assistant in the bank. Since the work on this table had increased considerably and it was not possible for one special assistant to cope with it. Shri Nigam was additionally put on this table to share the work of the Special Assistant, Shri R. S. Srivastava. The work of this table included— (a) posting of General Ledger; (b) writing of Cash Book; (c) preparation and checking of Reserve Bank's Statements; (d) Cash position; and (e) preparing and checking of returns. It was also added that the management had, for a considerably long time after promoting 3 Special Assistants Shri G. N. Nigam, Shri R. S. Srivastava and Shri M. C. Nigam w.e.f. 1st April 1968, continued to take purely routine clerical duties on the 3 tables including that of Accounts table from these 3 Special Assistants without calling upon them to do any of the duties prescribed for the Special Assistants under the Bi-partite Settlement and paid them the special allowance of Rs. 75 p.m. for the said period. It was also added that even now (10th January 1970) on many occasions when any of the permanent Special Assistant goes on leave, the relief special assistant is allowed to officiate in his place and is paid the relative special allowance of Rs. 75 per month on pro rata basis for the period he officiates, although during such officiating periods he continues to perform purely routine clerical duties and none of the duties of Special Assistants prescribed in the Bi-partite Settlement are taken from him. It was alledged that even in other branches of the bank in India including New Delhi branch the Special Assistants are performing purely clerical duties and they had not been assigned even one single duty of Special Assistant. The union's case was that Shri Nigam was sharing the duties of Shri R. S. Srivastava, a permanent Special Assistant on a key-table of the bank i.e. Accounts and the bank should be called upon to pay the special allowance of Rs. 75 per month to Shri Nigam w.e.f. 22nd December 1968 with any other benefits or relief as may be admissible to him. The Union also made a request for costs to the union aggregating Rs. 500.

7. The management in their counter-statement stated that the duties of Special Assistants listed on the Union's letter do not qualify Shri Nigam to receive a Special Assistant Allowance. Shri Nigam was never asked to check any Reserve Bank Statement or any returns. The management denied the Union's contention that Special Assistant had been performing merely clerical duties all the time. It was contended that there had been numerous occasions when the management had requested them to perform some of the duties listed in the Bi-partite Settlement. The work of discharging cheques in the Clearing Department was being done practically daily by a Special Assistant. The management concluded that the demand of Shri Nigam for payment of any part whatsoever of Special Assistant's allowance and his plea for a change in designation from clerk to Special Assistant is wholly unjustified, being not borne out by facts. The management disclaimed any liability for any costs which the union may have incurred in connection with the dispute.

8. The Union in their counter-statement stated that the Settlement dated 28th March 1968 between the Chartered Bank Organisation Employees Federation and the management of the Chartered Bank had a bearing on the present case, where it has been stipulated that the Special Assistants shall continue to do their routine clerical duties and functions and they shall be paid the Special Assistant's Allowance. The Union reiterated its earlier stand that 'in many cases the bank had not allotted any Special Assistants' duties to Special Assistants who draw allowance and performed only clerical duties and this they could do only under the terms of the aforesaid settlement with the Federation. Shri Nigam also did the same clerical duties, which a Special Assistant was performing and for which the Special Assistant was drawing a special allowance. The union's contention was that the clerical duties, which one special assistant was performing on Accounts table including preparation and checking of Reserve Bank returns, were bifurcated by the bank and were divided between the 2 persons, out of which one got the special allowance of Special Assistant while the other Shri Nigam, did not. According to the union the formula for determining seniority, as suggested by the union on 18th August, 1969, did not debar any employee from claiming any arrears of special allowance on the basis of work done by him.

9. During the hearing the parties reiterated the stand they had taken in their written statements. The union's case, in brief, was that by virtue of a settlement, dated 28th March, 1968, between the management and the Chartered Bank Organisation Employees Federation it was decided to create some posts of Special Assistants in the Chartered Bank and Kanpur got a quota of 3. The management appointed 3 Special Assistants including one Shri R. S. Srivastava, who was working on the Accounts table. Since the work on his table was found to be rather heavy, Shri Nigam was detailed to assist him. Both Shri R. S. Srivastava and Shri Nigam continued to perform the duties on the Accounts table among themselves and despite this the management did not pay Special Assistant Allowance to Shri Nigam though he did the same job which Shri R. S. Srivastava was doing, as there was no dividing line between the functions of both. It was also added that during the period Shri R. S. Srivastava was on leave for a week or so, Shri Nigam continued to hold the table independently. In a nutshell, their argument was that Shri Nigam was performing the same duties as were performed by Shri R. S. Srivastava and since the management was paying Special Assistant Allowance to Shri R. S. Srivastava, Shri Nigam was also entitled to the same. It was also contended that Special Assistant Allowance was being paid by the bank for doing jobs of routine nature. They cited 2 letters dated 5th July, 1969 and 24th December, 1968, received by them from Delhi Unit of their union. It was also added that Shri Nigam was a very senior employee and he in his own right, was entitled to Special Assistant Allowance. The complaint said to have been filed by Shri Nigam on 18th April, 1968, with the management claiming the allowance was also placed on record.

10. The management's case, on the other hand, was that 3 persons were earmarked for Special Assistant Allowance and the same was approved by the union vide their letter, dated 28th May, 1968. The workman was never asked to perform the duties which are to be performed by Special Assistant. According to them the workman was requested to visit Shri R. S. Srivastava in routine clerical duties. It was, of course, admitted by the management that no written order was issued by them in this regard. The management's representative further stated that according to the settlement, dated 28th March, 1968, it was up to the management to allot or not to allot any or all the duties of Special Assistants to a Special Assistant and it was, therefore, immaterial whether the persons who were paid Special Assistant Allowance were or were not performing the duties listed for them in the Bi-partite Settlement. They also placed on record a copy of the proforma of letter issued by the management to Special Assistants. The management representative concluded that Shri Nigam was asked to assist Shri Srivastava and he performed only routine clerical duties. The management's case was that the Special Assistants so designated by the management were occasionally performing duties which are the duties listed for them in the Bi-partite Settlement. The union disputed this matter and stated that this was only occasional. It was also denied by the union that Shri Nigam was asked to perform only routine clerical duties. It was, however, added on their part that during the period Shri Nigam was asked to work with Shri Srivastava, the latter was not required to perform any duty which is legitimately the duty of a Special Assistant as per B-partite Settlement.

11. I find that it is common ground that Shri Nigam assisted Shri Srivastava in performing his duties on the Accounts table, a table which had a lot of clerical work—so much that when Shri Nigam was detailed to assist him w.e.f. 22nd December 1968, there was nothing which attracted a special—assistant—allowance strictly in terms of Bi-partite Settlement. The union's case, in brief, is that since

Shri R. S. Srivastava was paid special allowance for doing the same work, Shri Nigam should also be paid. They have reinforced their argument by citing other tables and seats where special assistant allowance is being paid, though no duty, which can be said to be legitimately the duty of a special assistant, is being performed by them. The management's case, on the other hand, is that the management has a right to allot or not to allot any work meriting special assistant allowance under the Bi-partite Settlement to Special Assistants and it is immaterial what duties are performed by a workman who has been designated by the management as Special Assistant and who is being paid the special allowance.

12. The precise question for my arbitration is whether Shri Nigam is entitled to special assistant allowance of Rs. 75 per month. It is admitted by both the parties that by virtue of the settlement dated 28th March 1968 between the management and the Chartered Bank Organisation Employees Federation, the Kanpur Office could have a quota of 3 special assistants only and they do have 3 special assistants. The Union's claim for such allowance in favour of Shri Nigam amounts to raising this quota from 3 to 4, which obviously cannot be allowed because the settlement has been entered into between the management and the Chartered Bank Organisation Employees Federation—a body which is not before me. I find that the management has conclusively proved that it is up to them whether to allot any duties of special assistants to a particular special assistant or not and on this point there is no disagreement between the parties. As such, the payment of special assistant allowance to Shri Srivastava, who was being assisted by Shri Nigam and non-payment of the said allowance to Shri Nigam does not cause any injustice. It simply means that a particular special allowance (privilege) which is being given by the management to Shri Srivastava has been denied to Shri Nigam—the privilege which had been granted to Shri Srivastava by dint of the "guide lines for appointment of Special Assistants governed by Bi-partite Settlement." These guide-lines included at least 35 years of age, completion of 15 years of service, certain minimum educational qualifications, selection made by a Selection Committee etc. etc. In other words, Shri Nigam is not entitled to any special allowance since he has not performed any duties which have been listed to be the duties of Special Assistants as per Bi-partite Settlement, nor he is entitled to any such allowance on the plea that Shri Srivastava has been allowed the allowance for doing similar job because Shri Srivastava has been allowed the allowance not for holding a particular table but because of his seniority etc. etc. At this stage, I would express my personal opinion about the system employed by the management in employing special assistants. If I have been able to understand the existing system adequately, the management has picked out the specified number of persons to be the special assistants and they got this allowance whether or not they performed the duties of Special Assistants. If one special assistant performing a particular job is transferred to another table, he continues to draw the allowance though the workman manning his previous table did not get it nor the workman whose table he mans after the said shifting. In short, special assistant allowance has been earmarked for persons and not for posts. This is definitely an anomalous position. It has, at the same time, to be admitted that this system of the management has the approval of the union and the appointment of the existing 3 special assistants also bears their seal of approval vide the U.P. Bank Employees Union letter dated 26th May 1968. I would recommend to the management to discuss the matter with the workman's representatives again and place it on a sounder footing.

In the circumstances, I hold that Shri Nigam is not entitled to any Special Assistant allowance w.e.f. 22nd December 1968 and accordingly there is no case for changing his designation from Clerk to Special Assistant.

I award accordingly.

(Sd.) V. P. GUPTA,

Regional Labour Commissioner (Central) and
Arbitrator.

RLC's Office, Kanpur.

Dated the 23rd June, 1970.

[No. 24/26/69/LRIII.]

New Delhi, the 3rd July, 1970

S.O. 2348.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the

employers in relation to the National and Grindlays Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th June, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA.

REFERENCE NO. 7 OF 1970

PRESENT:

Employers in relation to the National and Grindlays Bank Limited,

AND

Their workmen.

PARTIES:

Mr. B. N. Banerjee—Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Shri M. S. Bala with Shri A. Roy Chowdhury.

On behalf of Workmen—Sri A. D. Singh, General Secretary, National Grindlays Bank Staff Union.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Banking.

AWARD

By Order No. 23/8/70/LRIII, dated February 26, 1970, the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour, Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the National and Grindlays Bank Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

“Whether the demand of Shri Anant Bahadur Singh a workman of the National and Grindlays Bank Limited, Calcutta for the Special Allowance admissible to Bill Collector is justified? If not, to what relief is he entitled and from when?”

2. The workmen, represented by the General Secretary, National and Grindlays Bank Staff Union, filed a written statement. In the said written statement it was pleaded that Anant Bahadur Singh, the concerned workman, was employed as a subordinate staff, in the Church Lane branch of the Bank, and was entrusted with the duties of a bill collector, with effect from the year 1945. It was further stated in the said written statement that the workman, Anant Bahadur Singh, was entrusted with the duty of “presenting different kinds of bills and collecting payments thereof from the offices of the Accountant General of West Bengal and Pension pay Master”. It was also stated that his duties included collection of cash in respect of Postal Orders and Compulsory Deposit bills from different Post Offices. By reason of the duties entrusted to him, it was claimed in the written statement, he was entitled to a special allowance of Rs. 13 per month, under the bipartite settlement of October 19, 1966. The grievance made before this Tribunal was that the management designated Anant Bahadur Singh as Cash Peon, although his duties were those of a bill collector, and paid cash allowance of Rs. 7 only per month, to him. His legitimate allowance of Rs. 13 was not paid to him in spite of repeated representations. On the aforesaid ground, it was claimed that the workman be paid an allowance of Rs. 13 per month less the amount of Rs. 7 per month, already received by him as cash allowance with effect from July 1966.

3. The management filed a written statement. In the said written statement it was denied that Anant Bahadur Singh was appointed as a bill collector or was entrusted by the management with the duties of a bill collector, during the relevant period. Paragraph 2 of the written statement by the management reads as follows:

“2. x x x x x, the Opposite Party craves reference to the list of duties of a “Bill Collector” as laid down in Appendix ‘B’, Part II, item (vii) of the Settlement dated 19th October, 1966 between Certain Banking Companies and their workmen. The aforesaid list is as under:

(i) Obtaining acceptance of bills of exchange, hundies etc., drawn on local parties or banks and collecting payments thereof;

- (ii) Collecting payments for cheques or postal orders etc., from banks or post office counters;
- (iii) Collecting cash not exceeding Rs. 600 against various instruments (if required).

The Opposite Party states that the Bills work of the branch concerned was transferred to the Bank's Main Branch at 19, Netaji Subhas Road sometime in 1959 and the question of performing any "Bill Collector's duties" during the period concerned (i.e. from July, 1966) for which the claim has been made, does not arise. Without prejudice to the above, the Opposite Party states that Sri Singh's duties include, *inter alia*, collection of cheques in payment of salary and pension bills, postal orders etc., from the office of the Accountant General of West Bengal, Pension Pay Master and Post offices and also cheques drawn on other banks outside the area served by the Bank's hand-delivery peons. As such, the duties performed by Shri Singh are different from those prescribed for Bill collectors in the Settlement dated 19th October, 1966."

In spite of all that was contained in paragraph 2 quoted above, it was pleaded in paragraph 3 that the duties of a bill collector were never performed by Anant Bahadur Singh and that the special allowance of Rs. 13/- was paid by the Bank only to those members of the Subordinate staff who performed the duties prescribed for bill collectors and not to others. It was lastly pleaded that the management re-allocated duties to Anant Bahadur Singh in order to bring them in conformity with those of cash-cum-cycle peon, by a letter dated January 17, 1967, which the workman signed in token of his acceptance.

4. The letter referred to above is Ex. 1 in this reference and reads:

"In supersession of any existing orders, instructions, etc. you are required to perform the duties and exercise the authorities prescribed for cash and Cycle Peon in the Bi-partite Agreement with effect from 16th January 1967 and as specified in the enclosed list over and above the routine duties and functions to be performed and discharged by you.

In terms of the Bipartite Settlement, a special allowance of Rs. 7 per month will be payable to you with effect from 16th January 1967 in lieu of your existing Special Allowance of Rs. 5 and Personal Pay Rs. 7-80. As the Special Allowance now payable is less than that formerly paid the difference will be commuted in terms of the Bipartite Settlement Para 5.17."

5. I have, at this stage, to refer to certain extracts from the Bi-partite settlement between the Bank managements and their workmen, dated October 19, 1966. The said agreement, as is well known, continued the earlier bank awards, including the Desai award, in so far as not specially modified by the agreement. In paragraph 5.3 of the said settlement it was provided as follows:—

"5.3. In supersession of paragraph 5.326 of the Desai Award the Special Allowance payable to members of the subordinate staff, for duties/ responsibilities as listed in Part II of Appendix B hereto, shall be as follows:—

(In Rupees per months)

Categories of Workmen	Class of Banks		
	A	B	C
i)	**	*	*
ii)	**	*	*
iii)	**	*	*
iv)	Cash Peons	7	6
v)	**	*	*
vi)	**	*	*
vii)	Bill Collectors	13	13
viii)			7
xi)			
x)			
xi)	**	*	*
xii)			
xiii)			

The employer Bank admittedly belongs to "A" class of Banks. In Appendix B, referred to in the above extract, the duties allotted to cash peons are:

"(iv) Cash Peons:

Persons required—

- (i) to take money orders, to buy stamps etc. which involves carrying of cash not exceeding of Rs. 400/- and to carry insured letters etc. to Post office;
- (ii) to stitch currency note bundles;
- (iii) to stitch and seal parcels or packets containing currency notes;
- (iv) to transit cash from the Bank to an office outside or vice-versa, if unaccompanied by a Watchman/Armed Guard."

The duties allotted to bill collectors are:

"(vii) Bill Collectors:

This work involves:

- (i) Obtaining acceptance of bills of exchange, hundies, etc. drawn on local parties or banks and/or collecting payments thereof.
- (ii) collecting payments for cheques or Postal Orders etc. from banks or Post Office counters.

They may also be required to collect cash not exceeding Rs. 600/- at a time against various instruments."

I need remind myself of two other provisions in the said agreement. It is stated in paragraph 5.8:

"5.8. A workman will be entitled to a special allowance if he is required to perform duty/duties and/or undertake the responsibilities listed against the category, irrespective of his designation/nomenclature or any general authority vested in him."

It is also stated in paragraph 5.11:

"5.11. Wherever a bank requires a workman to work in a post carrying a special allowance it will normally be done by an order in writing."

6. I have hereinbefore quoted paragraph 2 of the written statement filed by the employer Bank. That paragraph contains an admission which, on the face of it, goes a long way to help the workman. I may quote the admission over again, even at the cost of repetition:

".....the Opposite Party states that Sri Singh's duties include, *inter alia*, collection of cheques in payment of salary and pension bills, postal orders etc., from the offices of the Accountant General of West Bengal, Pension Pay Master and Post Offices and also cheques drawn on other banks outside the area served by the Bank's hand-delivery peons."

It appears from item (i) of bill collector's duties (hereinbefore quoted), that the work involves collecting 'payments for cheques or postal orders, etc., from banks or post office counters'. The part of the written statement quoted above includes collection of postal orders from post-office and collection of cheques drawn on other parties outside the area served by bank's hand-delivery peons. Mr. M. S. Bala, who represented the employer Bank, found himself in a somewhat tight corner when confronted with the statement but submitted that the passage quoted above contained a mistaken statement, which somehow inadvertently crept into the written statement. He submitted further:

- (a) that paragraph 1 contained the categoric statement denying that the concerned workman had been appointed as a bill collector or entrusted by the management with the duties of the bill collector.
- (b) that in paragraph 2 it was stated that bill work of the branch concerned stood transferred to the Bank's main branch at 19 Netaji Subhas Road from 1959 and the question of performing any bill collector's duties during the period concerned (i.e. from July 1966), for which the claim was made, did not arise.
- (c) immediately after the statement said to contain an admission, followed the following lines—"as such the duties performed by Sri Singh are different from those prescribed for bill collector in the statement dated 19th October, 1966."

On the above passages of the written statement, he submitted that all that preceded and followed the damaging statement were inconsistent therewith.

7. Now, an admission is binding on the party making the same but may also be shown to be wrong or mistaken. Mr. Bala is thus far correct that the admission in paragraph 2 does not fit in with all that preceded and followed the damaging statement. Therefore, there may be some substance in the submission of Mr. Bala that the Bank never intended to admit the claim of the concerned workman, otherwise it would not have begun or ended its pleading in the manner done.

8. A party, however, shall not be easily allowed to escape the consequences of an admission. Therefore, I have to go a little further into the matter. The workman deposed in the instant reference. In course of his deposition he said:

"My duties include collections against postal orders and National Savings certificates from post offices, collection of Pension bills from the office of the Accountant General. I also collect military pensions from Pension Pay Master. From the Accountant General's office I use to collect upto Rs. 20/- in cash and above that amount in cheques. I collect money from different post offices."

He was cross-examined by Mr. Bala. In course of cross-examination he admitted:

"At the time when cash peon's duties were allotted to me I put my signature on a letter (Ex. 1). I get cycle allowance for travelling by cycle. There are 4 or 5 other cash peons. Then says six or seven cash peons. Apart from me Trilok Dhami Singh, cycle peon, gets cycle allowance. The duties of cash peon include purchase of postal stamp from post office and carriage of the same to the banks office; they are to bundle up Government currency notes into bundles to requisite numbers. These are the works which they are required to do. Cycle is provided for doing work in post offices scattered about the city."

Questioned by the Tribunal he answered:

"I understood the contents of Ex. 1 and then put my signature thereon. I then understood that I would be employed to do the duties of cash peon and Cycle peon under the bi-partite agreement with effect from January 16, 1967 and for such duties would obtain Rs. 7/- as special allowance per month and a cycle allowance of Rs. 7.50 per month in lieu of my existing special allowance of Rs. 7/- and personal pay of Rs. 7.80."

What he stated in his examination in-chief might have brought him in the category of bill collector, at least duty of collecting payments against postal orders would have attracted the duties of a bill collector. He, however, did not stick to what is stated in his examination in-chief. In his cross-examination he stated that duties of a cash peon was allotted to him by letter Ex. 1. That letter is dated January 17, 1967. The duty of a cash peon does not entitle him to a cash allowance of Rs. 13/- per month.

9. A cash peon is entitled to an allowance of Rs. 7/- per month. Now, Paragraph 5.11 of the bi-partite agreement provides that whenever a workman is required to work in a post carrying special allowance, it will normally be done by an order in writing. Ex. 1 is the order in writing in the instant reference. That order calls upon the concerned workman to perform the duty of cash and cycle peon. He accepted that duty, according to his evidence, with full knowledge of what was written in Ex. 1. It is now too late to say that he was working in a different capacity and was entitled to a different allowance. He cannot aspire to succeed on the lapses of the management in drafting the written statement.

10. There is one other aspect of the matter which I need notice. In one of the paragraphs of the written statement, filed on behalf of the workman, it was alleged:

"That the Head cashier of the said branch who allotted duties of bill collector to Sri Singh agreed to a formula for the settlement of the above dispute and wanted sometime to get it approved from higher authorities before the Assistant Labour Commissioner, Central"

On this pleading, Mr. A. D. Singh, appearing for the workmen, contended that the Head cashier Anadi Nath Banerjee had agreed to grant bill collector's allowance

to the concerned workman, provided he gave up the claim for the years 1966-67. To prove this assertion Anadi Nath Banerjee was cited as a witness on behalf of the workmen. He denied and disputed the allegation in the written statement. Thus, there is no proof of the allegation quoted above and I put no value to the same. In my opinion, the workman has failed to prove his case. He can not aspire to succeed on an admission in the written statement of the management which in all possibility crept in by inadvertence for the reasons stated hereinbefore.

11. I, therefore, hold that the demand of Anant Bahadur Singh for special allowance admissible to bill collector is not justified and he is not entitled to any relief.

This is my award.

Dated, June 25, 1970.

B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.
[No. 23/8/70/LR.III.]

ORDERS

New Delhi, the 27th June 1970

S.O. 2349.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Hindusthan General Insurance Society Limited, Ranchi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of the Hindusthan General Insurance Society Limited, in dismissing from service Shri P. K. Das, Assistant in its Branch Office at Ranchi was justified. If not, to what relief is he entitled and from what date?”

[No. 40/17/70-L.R.I.]

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून 1970

का० आ० 2349:—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में हिन्दुस्तान जनरल इंश्योरेन्स सोसायटी लिमिटेड, रांची से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहिनीय समझती है ;

यतः अब, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-के अधीन गठित श्रौद्योगिक अधिकरण सं० 2, धनशाव को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है- ।

अनुसूची

“क्या हिन्दुस्तान जनरल इण्डोरेन्स सोसायटी लिमिटेड के प्रबन्धनत्र की, उसके शाखा कार्यालय में सहायक, श्री पी० के० दास को सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो वह किसी अनुतोप का और किसी तारीख से हकदार है?”

[स० 40/17/70-एल० आर० I]

New Delhi, the 30th June 1970

S.O. 2350—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No S.O. 1849, dated the 2nd May, 1970, namely—

- (1) After the words “the South India Insurance Company, Limited, Bombay”, wherever they occur, the words “including all its branches in India” shall be inserted,
- (2) In the Schedule to the said order, after item 17(r), the following item shall be inserted namely—
“18 Interim Relief”

[No 40/12/70-LR I]

S S SAHASRANAMAN, Under Secy.

तई दिल्ली, 30 जून, 1970

का० आ० 2350—श्रोतागिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के अम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश स० का० आ० 1849, तारीख 2 मई, 1970 में निम्नलिखित मर्यादित करती है, अर्थात्—

- (1) “साउथ इण्डिया इण्डोरेन्स कम्पनी, लिमिटेड, मुम्बई” शब्दों के पश्चात, जहा कही भी वे आए हों, “जिसमें इसकी भारत में सब शाखाएं सम्मिलित हैं,” शब्द अन्त स्थापित कर दिए जाएंगे।
- (2) उक्त आदेश की अनुसूची में मद 17 (द) के पश्चात निम्नलिखित मद अन्त स्थापित की जाएंगी, अर्थात्—
“18 अन्तरिम अनुतोप”

[स० 40/12/70-एल० आर०]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 27th June 1970

S.O. 2351—In pursuance of sub-section (2) of Section 9 of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Employment & Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1566 dated the 20th May, 1966, the Central Government hereby specified Shri P D Gaiha Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad, as the authority for the purposes of the said sub-section

2 This notification shall be deemed to have come into force on the 8th May, 1970

[No 6(12)/69-PFI]

B K SAKSENA, Under Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 1970

का० आ० 2351:—कोयला खान भविष्य निधि और बोनस अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 9 की उपधारा (2) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1566 तारीख 20 मई, 1966 को अधिकान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री पी० डी० गेहू, कोयला खान भविष्य निधि आयुष्ट, धनबाद, को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी विनियोग करती है ।

2. यह अधिसूचना 8 मई, 1970 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 6(12)-69-पी० एफ० 1]

बी० के० सक्सेना, प्रबर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 29th June 1970

S.O. 2352.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Vindhya Collieries (Private) Limited, Ramnagar Colliery, Post Office Ramnagar, District Shahdol, Madhya Pradesh and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd June, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT
JABALPUR

Dated June 4th, 1970

PRESENT:

Shri G. C. Agarwala, Presiding Officer.

CASE REF. No. CGIT/LC(R) (2) of 1970

PARTIES:

Employers in relation to Vindhya Collieries (P) Ltd. Ramnagar Colliery, P.O. Ramnagar Distt. Shahdol (M.P.).

Versus

Their workmen represented through:—

1. Koyala Khadan Shramik Sangh, Rajnagar Colliery.
2. M. P. Koyala Mazdoor Panchayat Branch, Ramnagar.

APPEARANCES:

For Employers:—

1. Shri P. S. Nair, Advocate.
2. Shri D. P. Agarwal, Manager, Ramnagar Colliery.

For Workmen:—

1. Shri Shiv Mangal Singh, President, Koyala Khadan Shramik Sangh.
2. Shri B. C. Singh, Vice President, M.P. Koyala Mazdoor Panchayat.

INDUSTRY: Coal Mine.

DISTRICT: Shahdol (M.P.).

AWARD

By Government Notification No. 1/4/69-LR.II, dated 19th January, 1970, the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), Government of India, referred the following matters of dispute,

as stated in the Schedule to the order of reference to this Tribunal, for adjudication:—

Matter of Dispute

SCHEDULE

“Whether the workmen employed in Messrs Vindhya Collieries (Private) Limited, Ramnagar Colliery are entitled to the following benefits:—

- (1) Variable Dearness Allowance at the rate of Rs. 1.47 per day from the 1st April, 1968.
- (2) Increments in the grade scales prescribed by the Wage Board from the 15th August, 1968.
- (3) Any additional payment from the 15th August, 1967 to October, 1967 when wages were increased.”

The reference was made under Section 10(2) of the I.D. Act, on the basis of an agreement by two Unions on one side namely M.P. Koyala Mazdoor Panchayat and Koyala Khadan Shramik Sangh and the employers M/s Vindhya Collieries (P) Ltd. Ramnagar Colliery on the other. In the reference order however only one Union M.P. Koyala Mazdoor Panchayat was mentioned as representing workmen. This omission was rectified and notice was issued to the other Union Koyala Khadan Shramik Sangh also. Both the Unions and the employers filed statements of claim followed by rejoinders on which certain issues were framed which need not be reproduced as the parties have compromised on this date of hearing.

There are three items under reference as stated above. For the V.D.A. the parties have agreed that it shall be paid at the rate of Rs. 1.32 per day.

For the second and the third items in the order of reference, parties agreed to abide by the settlement dated 28th December, 1969. The compromise is a fair and just settlement of the items of dispute and is accepted. An award in terms thereof is hereby recorded. Compromise settlement as also settlement dated 28th December, 1969 between Vindhya Collieries (P) Ltd. and the Koyala Khadan Shramik Sangh, Rajnagar & Bijuri Colliery annexure 'B' to employer's written statement shall form part of the award.

(Sd.) G. C. AGARWALA,
Presiding Officer.
4-6-1970.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

REF. NO. CGIT/LC(R) (2) /70

PARTIES:

Employers in relation to the management of Ramnagar Colliery, P.O. Ramnagar and their workmen represented by Madhya Pradesh Koyala Mazdoor Panchayat and Koyala Khadan Shramik Sangh.

The above named parties beg to submit as under:—

That the parties after mutual discussion have come to the conclusion that it is in the interest of workers and industrial peace to settle the dispute on the following terms:—

1. That the management shall pay V.D.A. at the rate of Rs. 1.32 per day from the date of publication of award. From 1st January, 1970 till the date of publication of the award, arrears at the rate of 21 paise per day i.e. the difference between Rs. 1.11 p. per day and Rs. 1.32 p. per day will be paid by the management within 30 days from the publication of the award. The workers representative will accept the above amount in full and final settlement of their claim and forgo the remaining portion of their claim.

Regarding increment in the general scale prescribed by the Wage Board and additional payment from 15th August 1967 to October, 1967 when wages were increased (items 2 and 3 of the order of reference), the parties agree that the matter stand settled by settlement dated 28th December, 1969 between M/s.

Vindhya Collieries P. Ltd., Ramnagar Colliery and the Koyala Khadan Shramik Sangh, Rajnagar and Bijuri Colliery (Annexure 'B' to the management's written statement), the terms of which are acceptable to all the parties.

PRAYER

It is therefore prayed that an award in terms of the above agreement may kindly be passed.

D. P. AGARWAL,
Manager,
Ramnagar Colliery.

SHIV MANGAL SINGH,
President,
Koyala Khadan Shramik Sangh,
Rajnagar Colliery.

B. C. SINGH,
Vice-President,
M.P. Koyala Mazdoor Panchayat,
Branch-Manager.
(and Authorised representative).

Jabalpur, dated 4-6-1970.

VERIFIED BEFORE ME

(Sd.) G. C. AGARWALA,
4-6-70.

PART OF THE AWARD

(Sd.) G. C. AGARWALA,
Presiding Officer,
4-6-1970.

ANNEXURE 'B'
FORM H

(See Rule 51)
Memorandum of Settlement

Name of the Parties:—

*For Employers in relation
to the Management of
Ramnagar Colliery.*

Shri D. P. Agarwal,
Manager,
Ramnagar Colliery.

For Workmen

Shri S. M. Singh,
President,
Koyala Khadan Shramik
Sangh, Rajnagar & Bijuri
Colliery.

Short recital of the case

In the month of July 1969, both the Unions namely Koyala Khadan Shramik Sangh and M.P. Colliery Mazdoor Panchayat agreed to refer the following disputes for Joint Adjudication under section 10(2) of the Industrial Dispute Act, 1947, namely:—

Whether the workmen employed in M/s Vindhya Collieries Private Ltd., Ramnagar Colliery are entitled to the following benefits:—

- (1) Variable D.A. at the rate of Rs. 1.47 per day from 1st April 1968.
- (2) Increments in the graded scales prescribed by the Wage Board from 15th August 1968.
- (3) Any additional payment from 15th August 1967 to October 1967 when wages were increased.

On the approach of large number of workers who are the member of Koyala Khadan Shramik Sangh and the Union, all the above three disputes referred to

Joint adjudication under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 were discussed mutually and to promote good and cordial relations, the management and the Union have agreed as follows:—

Terms of Settlement

1. Regarding increase V. D. A. the Union has agreed not to press the demand for the time being.

2. The Management agrees to give increments to time rated workers from 1st January, 1970 as per list attached and the amount shown against each. And the Union has agreed not to have any claim for the past period so far as increments are concerned.

The management shall pay the full arrears wages within one month from the date of this agreement from 15th August, 1967 to October, 1967 when the wages were increased to all the workers to whom the agreement is acceptable.

For Workmen

(Sd.) Illegible.

President.

Witnesses:

(Sd.) Illegible.

Welfare Officer,

Ramnagar Colliery.

Copy to:

1. The Asstt. Labour Commissioner (C), Jabalpur.
2. The Regional Labour Commissioner (C), Jabalpur.
3. The Chief Labour Commissioner (C), New Delhi.
4. The Secretary to the Govt. of India Ministry of Labour and Employment, New Delhi.

Monthly rated employees

Sl. No.	Name	Designation	Increment granted
1.	Shri U. K. P. Singh	L.W.O.	Rs. 20+20
2.	„ T. P. Banerjee	Cashier	Rs. 15+15
3.	„ R. P. Banerjee	Storekeeper	Rs. 10+10
4.	„ P. M. Yadav	G/Clerk	Rs. 7+7
5.	„ J. K. Tiwari	L/Clerk	Rs. 7+7
6.	„ A. N. Chatterjee	G/Clerk	Rs. 7+7
7.	„ Janeshwar Tiwari	G. Clerk	Rs. 7+7
8.	„ A. C. Gupta	G. Clerk	Rs. 7+7
9.	„ Sudama Tiwari	G. Clerk	Rs. 7+7
10.	„ A. K. Tiwari	G. Clerk	Rs. 7+7
11.	„ R. S. Marwaha	Surveyor	Rs. 25+00
12.	„ Ramnaresh Singh	Office peon	Rs. 3+3
13.	„ Purshottam Dubey	Office peon	Rs. 3+3
14.	„ Banaspati	Chaprasi	Rs. 3+3
15.	„ S. D. Rao	Chain Man	Rs. 4+4
16.	„ Arjun Tiwari	Chain Man	Rs. 4+4
17.	„ O. N. Pandey	Electrician	Rs. 10.40+10.40
18.	„ Bhaddoo	Fitter	Rs. 10+10
19.	„ Rambharosh Singh	L/Fitter	Rs. 5.20+5.20
20.	„ Surajballi	N. Guard	Rs. 3+3
21.	„ Jagat Narayan	Do.	Rs. 3+3
22.	„ Sheodas	Do.	Rs. 3+3
23.	„ Rambrichh	Do.	Rs. 3+3
24.	„ Muneshwar Tiwari	Do.	Rs. 3+3
25.	„ Surajdeo Singh	Do.	Rs. 3+3
26.	„ Ratnprasad	Do.	Rs. 3+3
27.	„ S. N. Dubey	Overman	Rs. 15+15
28.	„ J. M. Mehta	Do.	Rs. 15+15
29.	„ P. L. Kalia	Do.	Rs. 15+15
30.	„ N. Pandey	Do.	Rs. 15+15
31.	„ Chaman Singh	Do.	Rs. 15+15

Sl. No.	Name	Designation	Increment granted
32.	Shri Asharfi Pandey .	M/Sirdar	Rs. 7+7
33.	“ P. J. Permar .	Do.	Rs. 7+7
34.	“ Ganga Pandey .	Do.	Rs. 7+7
35.	“ Maheshwar Nonia .	Do.	Rs. 7+7
36.	“ S. D. Monia .	Do.	Rs. 7+7
37.	“ Ramji Singh .	Do.	Rs. 7+7
38.	“ Muni Dubey .	Do.	Rs. 7+7
39.	“ J. P. Nayak .	Do.	Rs. 7+7
40.	“ Ramlakhan Panika .	S/Fitter	Rs. 5+5
41.	“ R. D. Yadav .	A/Clerk	Rs. 7+7
42.	“ J. R. Banga .	Do.	Rs. 7+7
43.	“ P. N. Tiwari .	Do.	Rs. 7+7
44.	“ N. P. Singh .	Do.	Rs. 7+7
45.	“ Ram Singh .	Do.	Rs. 7+7
46.	“ G. S. Shrivastava .	Do.	Rs. 7+7
47.	“ J. N. Tiwari .	Do.	Rs. 7+7
48.	“ K. K. Tiwari .	Do.	Rs. 7+7

Time Rated Hazree Workers

1.	Shri Shankar .	Haulage Khalasi	Rs. 0.15+0.15
2.	“ Phakkar .	Do.	Rs. 0.15+0.15
3.	“ Jagiahir .	Do.	Rs. 0.15+0.15
4.	“ Madhusudhan .	Do.	Rs. 0.15+0.15
5.	“ Udeshi Mia .	Do.	Rs. 0.15+0.15
6.	“ Mohan .	Do.	Rs. 0.15+0.15
7.	“ Lachman .	Do.	Rs. 0.15+0.15
8.	“ Gurdeen .	Do.	Rs. 0.15+0.15
9.	“ Lalman .	Boiler Fireman	Rs. 0.20+0.20
10.	“ Mustakin .	Do.	Rs. 0.20+0.20
11.	“ Sukhai .	Do.	Rs. 0.20+0.20
12.	“ Corakh Nath .	General Maidoor	Rs. 0.10+0.10
13.	“ Ramganesh .	Do.	Rs. 0.10+0.10
14.	“ Chhotai .	Do.	Rs. 0.10+0.10
15.	“ Sugrim .	Do.	Rs. 0.10+0.10
16.	“ Bhola .	Do.	Rs. 0.10+0.10
17.	“ Ramsingh s/o Jhabboo .	Do.	Rs. 0.10+0.10
18.	“ Ramsingh s/o Biseshwar .	Do.	Rs. 0.10+0.10
19.	“ Ram Kumar .	Do.	Rs. 0.10+0.10
20.	“ Battao .	Do.	Rs. 0.10+0.10
21.	“ Awadhesh .	Do.	Rs. 0.10+0.10
22.	“ Mori .	Do.	Rs. 0.10+0.10
23.	“ Ramuwa .	Water Carrier	Rs. 0.10+0.10
24.	“ Nathoo .	General Maidoor	Rs. 0.10+0.10
25.	“ O. P. Tuknight .	Do.	Rs. 0.10+0.10
26.	“ Basudeo Pandey .	Do.	Rs. 0.10+0.10
27.	“ Rajnath Verma .	Lamp Incharge	Rs. 0.15+0.15
28.	“ Miloo .	Pick Sharpner	Rs. 0.15+0.15
29.	“ Sudhan .	Do.	Rs. 0.15+0.15
30.	“ Jhulan .	Do.	Rs. 0.15+0.15
31.	“ Pancham .	Drill Khalasi	Rs. 0.15+0.15
32.	“ Sita Ram .	Do.	Rs. 0.15
33.	“ Bishnath .	Do.	Rs. 0.15
34.	“ Alimuddin .	Do.	Rs. 0.15
35.	“ Kanhai .	Do.	Rs. 0.15+0.15
36.	“ Ganesha .	Do.	Rs. 0.15
37.	“ Gobardhan Tiwari .	Welder	Rs. 0.28+0.28
38.	“ Raju .	Sweeper	Rs. 0.12+C.12
39.	“ Muni Lal .	Do.	Rs. 0.12+0.12
40.	“ Ranglal .	Do.	Rs. 0.12
41.	“ Jabit .	Line Mistri	Rs. 0.15+0.15
42.	“ Jugal Tiwari .	Line Cooli	Rs. 0.12+0.12
43.	“ Ramdass .	Do.	Rs. 0.12+0.12
44.	“ Fatebahadur .	Line Cooli	Rs. 0.12+0.12
45.	“ Sita Tiwari .	Timber Cooli	Rs. 0.12+0.12
46.	“ Kashi Ram .	Carpenter	Rs. 0.20+0.20

Sl. No.	Name	Designation	Increment granted
47.	Shri Bajnath	Explosive Carrier	Rs. 0.1 + 20.12
48.	Chandpo	Do.	Rs. 0.12 + 0.12
49.	Ramanand	Do.	Rs. 0.12 + 0.12
50.	Reinadhar	Do.	Rs. 0.12 + 0.12
51.	Ramcharan Mishra	Fan Attendant	Rs. 0.15 + 0.15
52.	Prayag	Do.	Rs. 0.10
53.	Hira Lall	Do.	Rs. 0.20 + 0.20
54.	Kardhani	Do.	Rs. 0.20 + 0.20

Sd/- Illegible
28-12-69
Manager
Rannagar Colliery

Part of the Award.

G. C. AGARWALA,
Presiding Officer,
4-6-1970
[No. 1/4/69-LRII.]

ORDERS

New Delhi, the 29th June, 1970

S.O. 2353.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bhanora Colliery of Messrs Equitable Coal Company Limited, Post Office Charanpur, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

“Keeping in view the size of various tubs used in the pit at Bhanora Colliery of Messrs Equitable Coal Company Limited, Post Office Charanpur, District Burdwan, whether the demand of the surface piece-rated trammers represented by the Colliery Mazdoor Congress (HMS), Asansol for increase in the existing basic tub rate paid to them is justified? If so, what should be the basic tub rate and from what date?”

[No. 6/21/70-LRII.]

आवेदन

नई दिल्ली, 29 जून, 1970

का० आ० 2353:—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाध्य अनुसूची में विनियोगों के बारे में मैसेसी इकिटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकधर चरनपुर, जिला बर्द्दावान की भनोरा कोलियारी के प्रबन्धतान से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक शौचोगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, हमें, शौचोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार शौचोगिक अधिकारण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैर्गर्म इशिवटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर चरनपुर, जिला बर्दवान की भतोरा कोलियारी के गर्त में प्रयुक्त विभिन्न ट्रोणयानों (टबों) के आकार (साइज) को ध्यान में रखते हुए धरगतल मात्रानुपाती दर वाले ट्रेमर्स की, जिनका प्रतिनिधित्व कोलियारी मजदूर कांग्रेस (हि० म० स०), आसन्सोल करती है, उनको सदत्त की जाने वाली आधारिक ट्रोणयान (टब) दर में वृद्धि के लिए मांग न्यायोचित है ? यदि हां तो आधारित ट्रोणयान (टब) पर क्या होनी चाहिए और किस तारीख से होनी चाहिए ?”

[सं० 6/21/70-एल० आर० II]

S.O. 2354.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Bhagatdih Colliery, Post Office Jharia, Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, (No. 3) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act. १

SCHEDULE

“Whether the action of the management of East Bhagatdih Colliery, Post Office Jharia, Dhanbad in stopping their workman Shri Usman Mian, Lathe Machine helper from work with effect from the 19th November, 1969 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

[No. 2/58/70-LR.II.]

का० आ० 2354:—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपावदध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पूर्व भगतडीह कोलियारी, डाकघर भारिया, धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक श्रौद्धोगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बाल्लीय समझती है;

अतः, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार श्रौद्धोगिक अधिकरण (सं० 3) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“का० वृं भानडीह कोलियारी डाकघर भारिया, धनबाद के प्रबन्धतंत्र के, अन्ते कर्मकार, उस्मान मियां खगद मशीन बदलगार को 19 नवम्बर, 1969 ने बाम करने से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार फिस अनुशेष का हादार है ?

[सं० 2/58/70-एल० आर० II]

S.O. 2355.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Khas Bahiardih Colliery of Messrs Khas Bahiardih Coal Company, Post Office Tundoo, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Khas Bahiardih Colliery of Messrs Khas Bahiardih Coal Company, Post Office Tundoo, District Dhanbad in terminating the employment of Shri S. K. Bhaduri, Surveyor with effect from the 3rd October, 1969, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. 2/61/70-LRII.]

का० अ० 2355.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपावद्ध अनुसूची में विनियोजित विषयों के बारे में मैमर्स खाम बहियार इह कोल कम्पनी, डाकघर टुण्डू, जिला धनबाद की खाम बहियार इह कोलियारी के प्रबन्धनतंत्र में सन्वद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायानिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्ड द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण (सं० 3), धनबाद को न्यायानिर्णयन के लिए निर्देशित करनी है।

अनुसूची

‘क्या मैमर्स खास बहियार इह कोल कम्पनी, डाकघर टुण्डू, जिला धनबाद की खाम बहियार इह कोलियारी के प्रबन्धनतंत्र का थी एम० के० भादूरी, सर्वेक्षक के नियोजन को 3 अक्टूबर, 1969 से पर्यवहित करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?’

[मं० 2/61/70 एन० अर० II]

New Delhi, the 4th July 1970

S.O. 2356.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi and their workmen represented by National Coal Organisation Employees Association, Darbhanga House, Ranchi, Bihar;

And whereas the said employers and their workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 2nd June, 1970.

FORM C

Under Rule 7 of the Industrial Disputes (Central) Rules
Agreement

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act)
NAME OF PARTIES

Representing employers

Sri I. B. Sanyal, Chief Personnel Officer National Coal Development Corporation Ltd. Darbhanga House, Ranchi.

Representing workmen

1. Sri J. K. Bose, President, National Coal Organisation Employees Association, Darbhanga House, Ranchi.
2. Sri Abraham Mathews, General Secretary National Coal Organisation Employees Association, Darbhanga House, Ranchi.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Sri O. Venkatachalam, Chief Labour Commissioner (C), Department of Labour and Employment, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, New Delhi:—

(i) Specific matters:
in dispute.

Whether in view of various orders and circulars issued by the NCDC the date of increment fixed by the Management of NCDC in connection with implementation of Coal Wage Board as 15th August of each year is justified? If not, to what relief the workmen are entitled keeping in view the *ad hoc* increment granted by the Management with effect from 15th August, 1969.

(II) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or under-taking involved.

(i) Employers:—
National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi.

(iii) Name of the Union, if any representing the workmen in question.

(ii) Workmen as represented by:
National Coal Organisation Employees Association Darbhanga House, Ranchi.

(iv) Total number of workmen employed in the under-taking affected.

Details given against column (ii) above.

66,000 approx.

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.

40,000 approx.

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall make his award within a period of 6 months from the date on which this agreement is published in the Gazette of India or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period mentioned above, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the Parties.

I. B. SANYAL,
Chief Personnel Officer
National Coal Development Corporation Ltd.
Darbhanga House, Ranchi.

J. K. BOSE, President,
National Coal Organisation Employees Association
Darbhanga House, Ranchi.

ABRAHAM MATHEWS, General Secretary,
National Coal Organisation Employees Association
Darbhanga House, Ranchi.

Dated at Ranchi

This 16th day of May, 1970.

Witnesses.

- 1.
- 2.

[No. 8/93/70-LRII.]

T. K. RAMACHANDRAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जुलाई 1970

फा० आ० 2356.—यतः नेशनल कोल डिबेलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राची में सम्बद्ध नियोजकों और उनके वर्षकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व नेशनल कोल आर्गेनाइजेशन एम्पलायीज एसोसियेशन दरभंगा हाउस, राची, बिहार प्रती है, एक श्रीद्योगिक विवाद विद्यमान है;

। और यतः उक्त नियोजकों और वर्षकारों ने श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-की उपधारा (1) के उपबन्धों अनुमरण में उक्त विवाद को एक लिखित करार द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को माध्यम्यम के लिए निर्देशित कर दिया और उक्त माध्यम्यम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है।

। अतः अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 1-की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुमरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त माध्यम्यम् करार को, जो उसे 2 जून, 1970 को मिला था, एतद्वारा प्रकाशित करनी है।

प्रस्तुत ग

श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 1-की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुमरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त माध्यम्यम् करार को, जो

प्रकाशित करनी है।

नियोजकों के प्रतिनिधि

श्री श्राई० बी० सान्याल,

भुख्य कामिक अधिकारी,

नेशनल कोल डिबेलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड,

दरभंगा हाउस, राची ।

वर्षकारों के प्रतिनिधि

1. श्रो जै० के० बोस, अध्यक्ष

नेशनल कोल आर्गेनाइजेशन एम्पलायीज एसोसियेशन,

दरभंगा हाउस, राची ।

2 श्री अब्बाहम मैधूस, महासचिव,

नेशनल कोल आर्गेनाइजेशन एम्पलायीज एसोसियेशन,

दरभंगा हाउस, राची ।

पक्षकारों के बीच एतदद्वारा निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री ओ० बैंकग्रांचलम, मुख्य श्रम श्रायुक्त (सी) श्रम और रोजगार विभाग श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय, नई दिल्ली, के माध्यस्थम के लिए निदर्शित करने का करार किया गया है :—

(i) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : क्षण नेशनल कोल डिवेलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा जारी किए गए विभिन्न श्रादेशों और परिपनों की ध्यान में रखते हुए नेशनल कोल डिवेलपमेन्ट कार्पोरेशन के प्रबन्धतंत्र का कोयला मजदूरी बोर्ड के कार्यालयन के मम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष की वेतन बृद्धि की तारीख 15 अगस्त नियत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो प्रबन्धतंत्र द्वारा 15-8-1969 से मंजर की गई तदर्थ वेतन बृद्धि को ध्यान में रखने हुए, कर्मकार किम अनुदोष के हक्काः है ?

(ii) विवाद के पक्षकारों का व्योरा जिसमें ग्रन्तविलित स्थापन या उप-श्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है। (i) नियोजक :—नेशनल कोल डिवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राची। (ii) कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व करती है :— नेशनल कोल आर्गेनाइजेशन एम्पलायीज एसोसियेशन, दरभंगा हाउस, राची।

(iii) संघ का नाम, यदि कोई प्रणगत ऊपर स्तम्भ (iii) के भमाने व्योग दिया गया है। कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों लगभग 66,000 की कुल मंज्या

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या लगभग 40,000

हम यह करार और करते हैं कि मध्यस्थ का विनिष्चय हम पर आबद्धकर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट इस करार के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 6 महीने की कालावधि के भीतर या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा

बढ़ाया जाय, करेगा। यदि ऊपर वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं किया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतन्त्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर: [इ]

(आई० बी० सात्याल)

मुख्य कार्मिक अधिकारी,

नेशनल कोल इंजिनेयरमन्ट कारपोरेशन लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, रांची।

हस्ताक्षर

(जै० के० बोस)

म्रध्यक्ष

नेशनल कोल आर्गेनाइजेशन एम्प्लायीज एमोसियेशन
दरभंगा हाउस, रांची।

हस्ताक्षर

(अब्राहम मैथ्रस)

महासचिव,

नेशनल कोल आर्गेनाइजेशन एम्प्लायीज एमोसियेशन
दरभंगा हाउस, रांची।

रांची में सारीख

मई, 1970 का 16वां दिन

साक्षी

1. दुर्वाला

2. दुर्वाला

[सं० 8/93/70-एल० आर० II]

टी० के० रामचन्द्रन, अवर सचिव

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 1st July 1970

S.O. 2357.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act the employment in magnesite mines covered under the Mines Act, 1952 (35 of 1952), notice of its intention to do so having been given by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 295, dated the 13th January, 1970, as required by the said section.

[No. 2/51/67-LW.I.I.]

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

(अम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 1 जुलाई 1970

S.O. 2357.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस अधिनियम की अनूसूची के भाग 1 में

खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अन्तर्गत आने वाली मैगनेसाइट खानों में नियोजन को एनद्वारा जोड़ती है ; उसने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० शा० 295 तारीख 13 जनवरी, 1970 द्वारा, उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित, दे दी थी ।

[संख्या 2/51/67-एल० इस्यू० शार्ट० 1]

हस्त राज छाबड़ा, भवर सचिव ।

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 27th June 1970

S.O. 2358.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to acquire the evacuee properties specified in the Schedule hereto annexed in the State of Uttar Pradesh for a public purpose being a purpose connected with the relief and rehabilitation of displaced persons, including payment of compensation to such persons.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), it is notified that the Central Government has decided to acquire and hereby acquires the evacuee properties specified in the Schedule hereto annexed.

SCHEDULE

All properties in the State of Uttar Pradesh which have been allotted to the share of the Custodian in partition or have been vested in the Custodian under Section 11 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 as a result of adjudication by the Competent Officer, under the provisions of said Act upto 31st May, 1970, and in respect of which no appeals have been filed and if filed, have been rejected by the Appellate Officer.

[No. 2(21)/Comp. & Prop/61.]

(पुनर्वास विभाग)

(मुख्य बन्धेश्वर आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 27 जून, 1970

एस० श्रो० 2358 :—यतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि उत्तर प्रदेश में स्थित निष्कान्त सम्पत्तियों का, जो अनुबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट की गई है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन करना आवश्यक है । इस प्रयोजन का संबंध विस्थापित व्यक्तियों के राहत तथा पुनर्वास से है और इस में ऐसे व्यक्तियों को मुश्वाबजे का भूगतान करना भी शामिल है । अतः अब विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 12 में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने अर्जन का निर्णय कर लिया है और इसके द्वारा अनुबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट निष्कान्त सम्पत्तियों का अर्जन करती है ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में सभी सम्पत्तियां जो विभाजन में अभिरक्षक के हिस्से में शावृत्ति की गई हैं या निष्कान्त हित (पार्षदक्ष्य) अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन सभी अधिकारी के न्याय निर्णय के परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत 31-5-1970 तक अभिरक्षक के अधिकार में रही और जिनके बारे में कोई अपील दायर नहीं की गई हो और यदि की गई हो तो उन्हे अपील अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया हो ।

[संख्या 2(21)/कम्प एण्ड प्रौप०/61]

S.O. 2359.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to acquire the evacuee properties specified in the schedule hereto annexed in the State of Rajasthan for a public purpose being a purpose connected with the relief and rehabilitation of displaced persons, including payment of compensation to such persons.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 12 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), it is notified that the Central Government has decided to acquire and hereby acquires the evacuee properties specified in the schedule hereto annexed.

A-SCHEDULE

All properties in the State of Rajasthan which have been allotted to the share of the custodian in partition or have been vested in Custodian under Section 11 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951, as a result of adjudication by the Competent Officer under the provisions of the said Act, upto 31st May, 1970 and in respect of which appeals have not been filed, and if filed, have been rejected by the Appellate Officer.

[No. 22(13)/Comp.&Prop./61.]

JANKI NATH,
Settlement Commissioner & Under Secy.

एस० ओ० 2359.—यतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि राजस्थान में स्थित निष्कान्त सम्पत्तियों का, जो अनुबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट की गई हैं, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन करना आवश्यक है। इस प्रयोजन का संबंध विस्थापित व्यक्तियों के राहत तथा पुनर्वास से है और इस में ऐसे व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करना भी शामिल है। यतः अब विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने अर्जन का निर्णय कर लिया है और इसके द्वारा अनुबद्ध में निर्दिष्ट निष्कान्त सम्पत्तियों का अर्जन करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में सभी सम्पत्तियां जो विभाजन में अभिरक्षक के हिस्से में आवंटित की गई हैं या निष्कान्त हित (पार्थक्य) अधिनियम 1951 की धारा 11 के अधीन सक्तम अधिकारी के न्याय निर्णय के परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत 31-5-1970 तक अभिरक्षक के अधिकार में रही और जिनके बारे में कोई अपील दायर नहीं की गई हैं और यदि की गई हों तो उन्हें अपील अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया हो।

[संख्या 22(13)/कम्प० एण्ड प्रौप०/61]

जानकी नाथ,
बन्दोबस्त आयुक्त तथा अवर सचिव।

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 2nd July 1970

S.O. 2360.—In exercise of the powers conferred on the C.S.C. by sub-section (2) of Section 34 of the displaced persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (No. 44 of 1954), (hereinafter referred to as the said Act), the C.S.C. hereby delegates with immediate effect to the Regional Settlement Commissioner, (Central), Delhi, the following powers of the Chief Settlement Commissioner, namely:—

Powers under Sections 23, 24 & 28 of the said Act.

2. The said powers are to be exercised subject to the condition that the said Regional Settlement Commissioner shall not exercise any of such powers in relation to any matter in which an order has been made by him in his capacity as Regional Settlement Commissioner/Asstt. Settlement Commissioner Incharge or revise or review the orders of his predecessor.

[No. 11(1)/Comp. & Prop/68.]
RAJNI KANT, Chief Settlement Commissioner,

(पुनर्वास विभाग)

(मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 2 जुलाई 1970

एस० ओ० 2360.—विस्तापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) (जिसे इसके आगे उक्त अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा मुख्य बन्दोबस्त तत्काल क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त (केन्द्रीय) दिल्ली को मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की निम्नलिखित शक्तियाँ देते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की 23, 24 तथा 28 धाराओं के अन्तर्गत शक्तियाँ

2. उक्त शक्तियों का प्रयोग इस शर्त पर किया जाना है कि उक्त क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग किसी उम मामले में नहीं करेगा जिस पर उसने प्रभार क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त/सहायक बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में कोई आदेश दिया हो या अपने पूर्वाधिकारी के आदेशों का संशोधन या पुनरावलोकन किया हो।

[संख्या 11 (1) कम्प० एप्झ प्रीप०/68]

राजनी कान्त,

मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त।

पैट्रोलियम तथा रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय

(पैट्रोलियम और रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1970

का० ओ० 1100.—ग्रावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) यह आदेश पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन बनाये रखना) आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) यह 18 मार्च, 1970 को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषा :—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “तेल परियोधन कम्पनी” से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कम्पनियों में से कोई अभिप्रेत है;

(ख) “पैट्रोलियम उत्पाद” से अभिप्रेत है,—

(1) विमानन स्प्रिट,

(2) विमानन टरबाइन ईंधन,

(3) ईंधन तेल,

- (4) हाई स्पीड डीजल टेल,
- (5) हल्का डीजल टेल,
- (6) घटिया किरोसीन,
- (7) बढ़िया किरोसीन,
- (8) मोटर स्प्रिट,
- (9) नेप्पा,
- (10) बिलयक, जिसके अन्तर्गत खनिज नारपीन का टेल भी है,
- (11) जृट बैचिंग टेल,
- (12) मन्डर नारीमास्क टेल,
- (13) चाय सुखाने का टेल,
- (14) विट्मेन / एम्फाल्ट,
- (15) मोम।

3. पैट्रोलियम-उत्पादों के उत्पन्न को अन्तर्भुक्त करना :— (1) जहा केन्द्रीय सरकार का यह समाजान हो जाये कि ऐसा करना नांक हित में आवश्यक है वहाँ वह, निखित आदेश द्वारा, इस आदेश के प्रारम्भ से ठीक पहले के नीन वर्षों के दीरान किन्हीं बारह मास की निरन्तर कालावधि के लिए किसी पैट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन करने के कारबाह में लगे हुई किसी टेल परिशोधन कम्पनी को ऐसे उत्पाद का उत्पादन बनाये रखने या बनाये रखनाने के लिए निदेश दे सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार उक्त टेल परिशोधन कम्पनी से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध उपर्युक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर अभ्यावेदन, यदि कोई हो, करे।

- (2) (क) उपचाण्ड (1) के अधीन वाले नियम में किसी पैट्रोलियम उत्पाद के ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी मात्राओं में या अनुपातों में तथा ऐसी विनिर्दिष्टियों का जो उम्में विनिर्दिष्ट की जाये, उत्पादन बनाये रखने के लिए उपबन्ध हो सकेगा।
- (ख) ऐसे नियम, ऐसे अनुपूरक या आनुपंगिक उपबन्ध भी हो सकेंगे जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

(3) उपचाण्ड (1) के अधीन नियम जारी करने में केन्द्रीय सरकार निम्ननिखित को ध्यान में रखेगी, अर्थात् :—

- (1) ऐसे नियम को जारी करने की तारीख को टेल परिशोधन कम्पनी की, किसी पैट्रोलियम उत्पाद या उत्पादों का उत्पादन की सामर्थ्य;
- (2) उत्पादन में भौसमी उतार चढ़ावों को ध्यान में रखते हुए किसी एक वर्ष की कालावधि के दीरान कम्पनी के ऐसे उत्पाद या उत्पादों के उत्पादन की औसत मात्रा;
- (3) कोई अन्य सुसंगत बात।

4. नियमों का अनुपालन :—हर टेल परिशोधन कम्पनी, जिसे इस आदेश के अधीन नियम जारी किया जाये, ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी।

5. कतिपय परिस्थितियों में निवेश जारी भर्ती किया जायेगा :—अण्ड 3 में की किसी भात के होते हुए भी कोई भी निवेश किसी ऐसी कम्पनी को जारी नहीं किया जायेगा जो हड्डताल, घेराव, मशीनरी में लुटि या अपने नियंत्रण से परे की किसी अन्य परिस्थिति के कारण जिससे उत्पादन असंभव हो गया हो, किसी पेट्रोलियम उत्पाद या उत्पादों का उत्पादन करने से निवारित हो गई हो ।

[फा० सं० 42(8)/69—प्राई० ओ० सी०]

ई० एन० मंगतराम, विशेष सचिव ।